



बहिष्कार कथा बाहिष्कार भाजतेन  
**जन जन विचार**

जन जन की बात जन जन तक

# जन जन विचार

साप्ताहिक

WEEKLY TRILINGUAL NEWSPAPER

Language : Hindi, Assamese & English  
WEBSITE : www.janjanvichar.in



VOICE OF ALL, FOR ALL  
**JAN JAN VICHAR**  
WEEKLY

RNI Regd No. ASMUL/25/A2367::Guwahati, Friday, 14 August 2026 :: Year-1 Vol-31 Issue-10 :: शुक्रवार 14 अगस्त 2026। शक संवत् 1948। श्रावण। शुक्ल। द्वितीया। :: पृष्ठ-20। मूल्य - 15 रुपए

## जन चिंतन

धनेश्वर चौधरी

### कराहरही भारत माता

हम हर वर्ष तिरंगा फहराते हैं, देशभक्ति के गीत गाते हैं और भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। लेकिन क्या कभी ठहरकर यह भी पूछा है कि जिस भारत माता को हम मंचों से नमन करते हैं, उसकी हालत वास्तव में कैसी है? आज देश की तस्वीर में विकास की चमक जरूर दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, प्रदूषण, किसानों की चिंता, युवाओं की निराशा और आम आदमी की बढ़ती मुश्किलें भी नजर आती हैं।

राजनीति ने जनसेवा को पीछे छोड़कर आरोप-प्रत्यारोप और सत्ता की गणित को आगे कर दिया है। चुनाव आते ही जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के नाम पर भावनाएं भड़काई जाती हैं। जनता से विकास का वादा होता है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वही जनता फिर **शेष पृष्ठ 2 पर**

# बलूचिस्तान आजाद!

## भारत की ओर उम्मीद भरी नजरें-‘रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान’ को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने की अपील

जन जन विचार  
... नई दिल्ली

पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में स्वतंत्रता की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन ने अब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का रुख करना शुरू कर दिया है। 11 अगस्त को कथित ‘बलूचिस्तान स्वतंत्रता दिवस’ के अवसर पर बलूच नेतृत्व ने न केवल स्वतंत्रता के अपने दावे को दोहराया, बल्कि भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से प्रस्तावित ‘रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान’ को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की अपील भी की।

बलूच नेता मीर यार बलूच ने भारत और भारतीय मीडिया के प्रति सार्वजनिक रूप से आभार जताते हुए कहा कि भारतीय मीडिया



ने 11 अगस्त को बलूचिस्तान में मनाए गए स्वतंत्रता दिवस से जुड़े कार्यक्रमों को प्रमुखता दी। उन्होंने भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के उस बयान का भी स्वागत किया, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर तथा उसके नियंत्रण वाले अन्य क्षेत्रों में मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की जरूरत पर जोर दिया गया था। **शेष पृष्ठ 7 पर**

## आजादी के जश्न पर एयर स्ट्राइक

नई दिल्ली। बलूचिस्तान में स्वतंत्रता की मांग को लेकर चल रहा संघर्ष अब एक बार फिर बेहद हिंसक मोड़ पर पहुंच गया है। 11 अगस्त को ‘स्वतंत्रता दिवस’ के रूप में मनाए गए कार्यक्रमों के बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कथित हवाई कार्रवाई और उसके जवाब में बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) के हमलों ने क्षेत्र में तनाव और बढ़ा दिया है। स्थानीय सूत्रों और कार्यकर्ताओं के दावों के अनुसार, पाकिस्तानी हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 21 नागरिकों की मौत हुई है। हालांकि, इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि पाकिस्तानी विमानों ने केवल सशस्त्र समूहों के ठिकानों को निशाना बनाने के बजाय आबादी वाले क्षेत्रों में **शेष पृष्ठ 5 पर**

## GAURANSHI INDUSTRIES

Purity in Every Drop, Nature in Every Product.

## Happy INDEPENDENCE DAY 2026

75 YEARS OF FREEDOM PROGRESS PRIDE

Let's honor the freedom we enjoy and the progress we continue to build.

Proud to be Indian. Proud to be Natural.

*Jai Hind!*

NO ADDITIVES  
BOOSTS IMMUNITY  
RICH IN ANTIOXIDANTS  
ECO FRIENDLY

RAW & UNPROCESSED  
PURE & NATURAL  
DIRECTLY FROM OUR FARMS  
TRUSTED BY THOUSANDS

Let's Build a Stronger, Greener & Healthy India Together.  
**HAPPY INDEPENDENCE DAY!**  
JAI HIND! VANDE MATARAM!

NAME: MAKHANA (FOX NUT SUPERFOOD) ASSAM CTC TFA ASSAM CTC TFA  
SIZE: 200gm 250gm 100gm

NAME: MUSTARD HONEY LITCHI HONEY WILD FOREST HONEY  
SIZE: 200gm 200gm 200gm

3rd Floor, IIT Road, Jayguru, Amingaon, Kamrup, Assam - 781031, India

Contact : +91-88224 20619

E-Mail : gauranshiind@gmail.com  
www.gauranshiindustries.com

## धन दिशा

आपातकालीन निधि  
मुश्किल वक्त के लिए

अचानक नौकरी चली जाए, परिवार में किसी को अस्पताल जाना पड़े, कारोबार में नुकसान हो जाए या घर की कोई महंगी वस्तु अचानक खराब हो जाए—ऐसे समय में सबसे बड़ी चिंता होती है धन की। जीवन में आने वाली ऐसी अनिश्चित परिस्थितियों से निपटने के लिए आपातकालीन निधि यानी संकट के समय काम आने वाली बचत बेहद जरूरी है। यह केवल बचत नहीं, बल्कि आर्थिक सुरक्षा का ऐसा कवच है, जो मुश्किल समय में व्यक्ति को कर्ज लेने और दूसरों पर निर्भर होने से बचा सकता है।

आज की तेज रफ्तार जिंदगी में आमदनी भले बढ़ रही हो, लेकिन खर्च भी लगातार बढ़ रहे हैं। घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई, बिजली-पानी के बिल, बीमा, मासिक किस्त, दवाइयां और रोजमर्रा के खर्च के बीच अचानक आने वाला बड़ा खर्च पूरे घरेलू बजट को बिगाड़ सकता है। ऐसे समय में आपातकालीन निधि आर्थिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

## आपातकालीन निधि क्या है ?

आपातकालीन निधि वह धनराशि है जिसे केवल वास्तविक संकट के समय इस्तेमाल करने के लिए अलग रखा जाता है। इसका उपयोग घूमने-फिरने, महंगे सामान खरीदने, त्योहार की खरीदारी या अन्य गैर-जरूरी खर्चों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

आमतौर पर कम से कम तीन से छह महीने के आवश्यक खर्च के बराबर राशि आपातकालीन निधि में रखना उपयोगी माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति की नौकरी अस्थिर है, वह अपना कारोबार करता है या परिवार में केवल एक व्यक्ति कमाता है, तो इससे अधिक राशि सुरक्षित रखना भी समझदारी हो सकती है।

मान लीजिए किसी परिवार का आवश्यक मासिक खर्च 40 हजार रुपए है। छह महीने के खर्च के हिसाब से उसे लगभग 2 लाख 40 हजार रुपए की आपातकालीन निधि का लक्ष्य रखना चाहिए।

## शुरुआत छोटी हो, लेकिन नियमित हो

कई लोग आपातकालीन निधि इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि पहले बड़ी रकम जमा करनी होगी। वास्तव में ऐसा नहीं है। शुरुआत छोटी राशि से भी की जा सकती है।

हर महीने अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा अलग खाते में जमा करना बेहतर तरीका है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति हर महीने 5 हजार रुपए अलग रखता है तो एक वर्ष में 60 हजार रुपए जमा हो जाएंगे। समय के साथ यही राशि एक मजबूत आर्थिक सुरक्षा कवच बन सकती है। सबसे जरूरी बात है—नियमित बचत।

## धन कहाँ सुरक्षित रखें ?

आपातकालीन निधि का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर धन आसानी से उपलब्ध कराना है। इसलिए इस राशि को ऐसे सुरक्षित साधन में रखना चाहिए, जहां जोखिम कम हो और आवश्यकता पड़ने पर धन आसानी से निकाला जा सके। अलग बचत खाते या अन्य सुरक्षित और आसानी से उपलब्ध विकल्पों का उपयोग किया जा सकता है। आपातकालीन निधि को अत्यधिक जोखिम वाले निवेश में रखना उचित नहीं है, क्योंकि बाजार में गिरावट के समय ही यदि धन की जरूरत पड़ गई तो नुकसान उठाना पड़ सकता है।

## -कोमल जैन

पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट, संस्थापक, वेल्थप्लायर्स- मो. 9004510577

युवा समाजसेवी विकास गुप्ता के  
पिता नागरमल गुप्ता का निधनजन जन विचार  
...क गुवाहाटी

युवा समाजसेवी एवं मीडिया से जुड़े विकास गुप्ता के पिता नागरमल गुप्ता का गत 4 अगस्त को सुबह आकस्मिक निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। उनके निधन की खबर से परिजनों, मित्रों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और परिचितों में शोक की लहर दौड़ गई।

परिवार के अनुसार, उन्होंने अपने जीवनकाल में मानव सेवा को भावना को महत्व दिया। उनके पुत्रों ने पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए मरणोपरांत उनका नेत्रदान करवाया। परिवार के इस निर्णय को लोगों ने मानवीय संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी की प्रेरणादायी मिसाल बताया।

नागरमल गुप्ता अपने पीछे दो पुत्रों, दो पुत्रियों सहित भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। परिचितों के अनुसार वे जिंदादिल, मिलनसार और सतल स्वभाव के व्यक्ति थे। केदार रोड, आठगांव, एटी रोड सहित आसपास के क्षेत्रों में उनकी लंबे समय से अच्छी पहचान थी।

## खिलाड़ियों का सम्मान

रोहा। छठी नगांव जिला कराटे अंतर-क्लब चैंपियनशिप में 11 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 16 पदक जीतने वाले बौद्धिधर्मा कराटे क्लब के खिलाड़ियों को मानव अधिकार संग्राम समिति (मास) की रोहा आंचलिक समिति ने सम्मानित किया। शंकरदेव शिशु विद्या निकेतन में आयोजित कार्यक्रम में मास के कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद डेका सहित प्रतिनिधिमंडल ने खिलाड़ियों का फूलाम गामोछा से सम्मानित किया। मुख्य प्रशिक्षक नित्य कुमार पातर, प्रशिक्षक प्रीयम मजूमदार, क्लब सचिव संजीव नाथ और पत्रकार सोयल खेतान को भी सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में 14 में से 13 खिलाड़ियों ने पदक जीते।



उनके पुत्र संजय कुमार गुप्ता और विकास गुप्ता सामाजिक गतिविधियों से जुड़े रहे हैं। कनिष्ठ

पुत्र विकास गुप्ता समाजसेवा के साथ मीडिया क्षेत्र में भी सक्रिय हैं और विभिन्न सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों में अपनी भागीदारी निभाते रहे हैं।

नागरमल गुप्ता के निधन का समाचार मिलते ही बड़ी संख्या में लोग उनके निवास पर पहुंचे और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। लोगों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए परिवार को इस कठिन समय में धैर्य प्रदान करने की कामना की।

## राशिफल

14 से 20 अगस्त 2026 | विक्रम संवत् 2083- मास : श्रावण, पक्ष : शुक्ल, तिथि : द्वितीया

**मेष :** इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। मेहनत का उचित परिणाम मिलने के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें। परिवार में किसी सदस्य के साथ चल रहा मतभेद दूर हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है।

**वृषभ :** आर्थिक मामलों में सप्ताह लाभदायक रह सकता है। रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर सहयोग मिलेगा। व्यापार में नया अवसर सामने आ सकता है। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा।

**मिथुन :** इस सप्ताह आपको कार्यक्षमता और आत्मविश्वास बढ़ेगा। नई योजनाओं पर काम शुरू करने का अवसर मिल सकता है। धन संबंधी मामलों में सावधानी जरूरी है। किसी मित्र या परिचित से महत्वपूर्ण सहायता मिल सकती है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा।

**कर्क :** सप्ताह की शुरुआत थोड़ी व्यस्त रह सकती है, लेकिन बाद में परिस्थितियां आपके पक्ष में आएंगी। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी की संभावना बन सकती है। व्यापारियों को लाभ मिल सकता है। परिवार में किसी शुभ समाचार से प्रसन्नता होगी।

**सिंह :** आपके लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास और सफलता से भरा रह सकता है। कार्यक्षेत्र में आपको प्रतिभा की सराहना होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। परिवार में आपका प्रभाव बढ़ेगा।

**कन्या :** इस सप्ताह आपको योजनाबद्ध तरीके से काम करने की आवश्यकता होगी। काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन मेहनत का परिणाम भी मिलेगा। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। खान-पान पर विशेष ध्यान दें।

**तुला :** सप्ताह आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। नौकरी या व्यापार में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से संपर्क भविष्य में लाभदायक साबित होगा।

**वृश्चिक :** इस सप्ताह अपने काम में अधिक ध्यान और धैर्य रखने की जरूरत है। कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी से मतभेद हो सकता है, इसलिए संयम रखें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें।

**धनु :** यह सप्ताह आपके लिए उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा। नौकरी और व्यापार में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक लाभ के साथ खर्च भी बढ़ सकता है।

**मकर :** काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आपको मेहनत बेकार नहीं जाएगी। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आर्थिक मामलों में स्थिरता आएगी। परिवार के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे।

**कुंभ :** आपके लिए यह सप्ताह नए अवसरों का संकेत दे रहा है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापार में नए संपर्क लाभदायक रहेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

**मीन :** सप्ताह की शुरुआत में कुछ मानसिक तनाव रह सकता है, लेकिन धीरे-धीरे परिस्थितियां बेहतर होंगी। कार्यक्षेत्र में मेहनत का परिणाम मिलेगा।

## सप्ताह के पर्व/त्योहार

- 14 अगस्त (शुक्रवार) : धर्म सम्राट स्वामी करपाती जयंती
- 15 अगस्त (शनिवार) : भारत का स्वतंत्रता दिवस
- 16 अगस्त (रविवार) : वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत
- 17 अगस्त (सोमवार) : श्री नाग पंचमी
- 19 अगस्त (बुधवार) : श्री गोस्वामी तुलसीदास जयंती



● ज्योतिर्विद आचार्य अखिलेश्वर शुक्ल  
भाग्योदय : पहला तल्ला, सेंट्रल प्लाजा, एमएस रोड  
फैंसी बाजार, गुवाहाटी-781001 मो.-94350 40387

## पृष्ठ 1 का शेरांश...

## कराह रही भारत माता

अपने रोजमर्रा के संघर्षों में अकेली छोड़ दी जाती है।

भारत माता तब भी कराहती है जब गरीब इलाज के लिए जमीन बेचता है, युवा डिग्री लेकर रोजगार की तलाश में भटकता है और किसान अपनी मेहनत को उचित कीमत के लिए संघर्ष करता है। वह तब

भी कराहती है जब कानून का इस्तेमाल कमजोर पर कठोर और प्रभावशाली पर नरम दिखाई देता है।

देशभक्ति केवल नारे लगाने में नहीं, बल्कि व्यवस्था को ईमानदार बनाने में है। तिरंगे को सलाम करने का अर्थ है उस नागरिक का सम्मान करना जो उसके नीचे सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन चाहता है। आज जरूरत जर्जन से अधिक आत्ममंथन की है। भारत माता को नारों की नहीं, न्याय, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ईमानदार शासन और संवेदनशील समाज की जरूरत है। यही सच्ची देशभक्ति है।



# कपूरचंद पाटनी : एक पता जो कभी मिटेगा नहीं

जन जन विचार  
... गुवाहाटी

**‘यदि मैं कभी खो जाऊँ, तो तुम मुझे  
कहाँ खोजोगे?’**

कपूरचंदजी पाटनी की कविता ‘मेरा पता’ का यह सवाल आज उनके निधन के बाद जैसे पूरे समाज से पूछा जा रहा है। जिस कवि ने कभी अपने ‘पते’ की तलाश शब्दों में की थी, उनके जाने के बाद शायद सबसे बड़ा उत्तर यही है कि कुछ लोगों का पता किसी घर, सड़क या शहर में नहीं होता। उनका पता उनके कर्म होते हैं, उनकी रचनाएँ होती हैं और वे लोग होते हैं, जिनके जीवन को उन्होंने अपने विचार, स्नेह और सेवा से छुआ होता है।

कपूरचंदजी पाटनी ऐसे ही व्यक्तित्व थे। साहित्य उनके लिए केवल अभिव्यक्ति नहीं था, शिक्षा केवल संस्था नहीं थी और समाजसेवा केवल दायित्व नहीं। इन तीनों के बीच उन्होंने अपने जीवन को ऐसी रेखा खींची, जिसमें ज्ञान के साथ संवेदना, परंपरा के साथ आधुनिक दृष्टि और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ मानवीय आत्मीयता दिखाई देती है।

उनका जाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उनके साथ एक व्यक्ति ही नहीं गया, बल्कि एक ऐसा जीवंत संवाद भी थम गया, जो साहित्य, शिक्षा, समाज और संस्कृति के अनेक क्षेत्रों में लंबे समय से सक्रिय था।

**असम को कर्मभूमि नहीं  
जीवनभूमि बनाया**

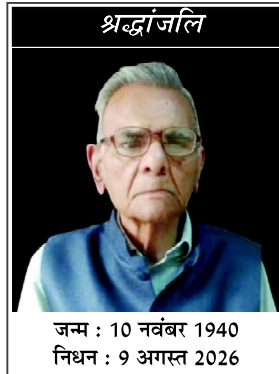
कपूरचंदजी के पूर्वज राजस्थान के सीकर क्षेत्र से आकर असम में बसे थे। लेकिन असम उनके लिए केवल रहने या काम करने की जगह नहीं रहा। पलाशबाड़ी की मिट्टी, ब्रह्मपुत्र की सांस्कृतिक धारा, असमिया भाषा और यहां के सामाजिक जीवन ने उनके व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने असम को अपनी आत्मीय भूमि के रूप में स्वीकार किया और इसी आत्मीयता ने उनके साहित्यिक व्यक्तित्व को भी आकार दिया।

10 नवंबर 1940 को जन्मे कपूरचंदजी बचपन से ही मेधावी थे। पलाशबाड़ी के आर. बी. हाई स्कूल से उन्होंने असमिया माध्यम में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और असमिया विषय में लेटर मार्क प्राप्त किया। आगे उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और कानून का अध्ययन भी किया। लेकिन शिक्षा उनके लिए केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं रही। वे ज्ञान को समाज और आने वाली पीढ़ियों के निर्माण का माध्यम मानते थे।

यही दृष्टि बाद में उनके सार्वजनिक जीवन की पहचान बनी।

**एक विद्यालय, कई पीढ़ियाँ  
और एक दूरदर्शी सोच**

श्री दिगंबर जैन विद्यालय, गुवाहाटी के साथ कपूरचंदजी का दशकों पुराना संबंध रहा। वर्ष 1972 से विद्यालय के सचिव के रूप में उन्होंने इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विद्यालय के विस्तार से लेकर



**जन्म : 10 नवंबर 1940  
निधन : 9 अगस्त 2026**

अंग्रेजी माध्यम की शुरुआत और विद्यार्थियों के शैक्षणिक भविष्य तक उनकी दृष्टि स्पष्ट और दूरगामी थी।

उनके लिए किसी संस्था की सफलता केवल भवन, प्रशासन या व्यवस्था से नहीं मापी जाती थी। संस्था की वास्तविक सफलता विद्यार्थी के भविष्य में दिखाई देती है—और यही सोच उनके कार्यों में दिखाई देती रही।

पलाशबाड़ी से गुवाहाटी आने के बाद भी विजयनगर जैन समाज से उनका आत्मीय जुड़ाव बना रहा। धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में वे रुचि लेते और सहयोग करते रहे। उनके लिए संबंध केवल परिचय नहीं थे; उन्हें निभाना जीवन का हिस्सा था।

**जब असमिया भाषा में  
धड़कने लगा एक मन**

कपूरचंदजी के जीवन की सबसे विशिष्ट पहचान उनका साहित्यिक व्यक्तित्व था। असमिया भाषा के प्रति उनका अनुराग गहरा और आत्मीय था। उन्होंने असमिया को केवल लिखने-पढ़ने की भाषा के रूप में नहीं देखा, बल्कि उसकी सांस्कृतिक आत्मा से संवाद किया।

यही कारण है कि उनकी कविताओं में असम की मिट्टी से जुड़ा हुआ एक संवेदनशील मन दिखाई देता है। वे असम साहित्य सभा के आजीवन सदस्य रहे और साहित्यिक जगत में सम्मान के साथ स्मरण किए जाते रहे।

‘श्रुतिये सुधिसे’, ‘जेतिया सूर्जर आदातलतत हिहतर विचार होबो’ (जब सूर्य की अदालत में उनका फैसला होगा), ‘सराइर मात’ (चिड़िया की आवाज) और ‘मोर ठिकना’ (मेरा पता) जैसी उनकी रचनाएँ उनके काव्य-संसार के अलग-अलग आयामों को सामने लाती हैं। प्रकृति, मनुष्य, सामाजिक संघर्ष, स्मृति, सृजन और आत्मचिंतन उनके लिए अलग-अलग विषय नहीं थे; वे जीवन के एक ही व्यापक अनुभव के हिस्से थे।

**‘सराइर मात’**

**और जीवन का दर्शन**

उनकी कविता ‘सराइर मात’ में एक अत्यंत गहरी जीवन-दृष्टि दिखाई देती है। कविता में चिड़िया ऊँचाइयों की ओर उड़ती है, लेकिन एक सीमा के बाद उसे अपनी ही आवाज सुनाई देना बंद हो जाता है। अंततः कविता एक महत्वपूर्ण संदेश देती है—‘इतनी ऊँचाई

तक उड़ो, जहां अपनी आवाज स्वयं सुन सको।’

यह केवल एक काव्य-पंक्ति नहीं है। कपूरचंदजी के जीवन को देखें तो यह उनके व्यक्तित्व का भी रूपक बन जाती है।

उन्होंने संस्थागत जिम्मेदारियाँ निभाईं, सामाजिक सम्मान पाया, साहित्य में अपनी पहचान बनाई और अनेक क्षेत्रों में सक्रिय रहे। लेकिन इन ऊँचाइयों के बीच उन्होंने अपनी मानवीय जड़ों और अपनी आंतरिक आवाज को नहीं खोया।

शायद यही कारण है कि उनकी कविता पढ़ते हुए उनके व्यक्तित्व की झलक भी दिखाई देती है।

**‘मोर ठिकना’—जिसका उत्तर  
उन्होंने खुद लिख दिया था**

कपूरचंदजी की कविता ‘मोर ठिकना’ आज उनके निधन के बाद सबसे अधिक अर्थपूर्ण लगती है।

कवि पूछता है—  
**‘यदि मैं कभी खो जाऊँ, तो तुम मुझे  
कहाँ खोजोगे?’**

आज यही सवाल उनके जाने के बाद सामने है।

उन्हें कहाँ खोजा जाए?  
उनकी पुस्तकों में?  
उनकी कविताओं में?  
उन संस्थाओं में, जिन्हें उन्होंने वर्षों तक अपना समय दिया?  
उन विद्यार्थियों में, जिनके भविष्य की चिंता की?

उन सामाजिक कार्यों में, जिनसे उनका जुड़ाव रहा?

या उन लोगों की स्मृतियों में, जिन्हें उन्होंने स्नेह, सलाह और प्रोत्साहन दिया?  
उत्तर शायद—इन सभी में।

‘मोर ठिकना’ में कवि अपने अस्तित्व की तलाश करता है। कभी सड़क किनारे पड़े काले-सफेद पत्थर में, कभी टूटे सपनों के टुकड़ों में, कभी सृजन के बीजों में और कभी स्मृतियों के बीच। यह कविता केवल किसी व्यक्ति के पते की खोज नहीं, बल्कि मनुष्य की पहचान और उसके जीवन की सार्थकता की खोज भी है।

कपूरचंदजी के जीवन को सामने रखकर देखें तो लगता है कि उन्होंने अपने प्रश्न का उत्तर बहुत पहले ही दे दिया था।

उनका पता अब किसी घर की चौखट पर नहीं है।

वह साहित्य में है।

वह शिक्षा में है।

वह सेवा में है।

वह संस्कार में है।

और उन लोगों की स्मृतियों में है, जिनके जीवन को उन्होंने किसी न किसी रूप में समृद्ध किया।

**साहित्यकार ही नहीं**

**साहित्यिक संस्कार के वाहक**

कपूरचंदजी की साहित्यिक भूमिका उनकी अपनी रचनाओं तक सीमित नहीं थी। वे दूसरे लेखकों की रचनाओं को भी ध्यानपूर्वक पढ़ते और उनके लेखन को प्रोत्साहित करते थे।

उनकी विशेषता यह थी कि वे केवल प्रशंसा करके आगे नहीं बढ़ जाते थे। वे लेखक को यह भी बताते थे कि किसी विषय को अधिक प्रमाणिक, संदर्भपूर्ण और व्यापक कैसे बनाया जा सकता है। जैन धर्म और दर्शन से संबंधित लेखों पर उनकी प्रतिक्रियाएँ उनके गंभीर अध्ययन और साहित्यिक दृष्टि को दर्शाती थीं।

उनके व्यक्तित्व में प्रशंसा के साथ परिष्कार और स्नेह के साथ अनुशासन था। वे साहित्य को शब्दों की सजावट नहीं, बल्कि विचारों के जीवंत संवाद के रूप में देखते थे।

यही कारण है कि उनका साहित्यिक योगदान केवल उनकी पुस्तकों और कविताओं तक सीमित नहीं माना जा सकता। उन्होंने लेखकों को पढ़ा, उनसे संवाद किया और उन्हें बेहतर लिखने के लिए प्रेरित किया।

**समाजसेवा : विचार से कर्म तक**

कपूरचंदजी का सामाजिक जीवन भी उनके साहित्यिक जीवन जितना ही व्यापक था। कामरूप चैंबर्स ऑफ कॉमर्स, भारत विकास परिषद, श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा और विभिन्न साहित्यिक-सामाजिक मंचों से उनका जुड़ाव रहा।

अहिंसा और शाकाहार के प्रचार-प्रसार के लिए ‘जीवन ज्योति’ जैसी संस्था की स्थापना उनके सामाजिक सरोकारों की गंभीरता को दर्शाती है।

श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय मुखपत्र ‘जैन गजट’ के वे वर्षों तक प्रधान संपादक रहे। उनके संपादकीय दृष्टिकोण में परंपरा के प्रति सम्मान और समकालीन प्रश्नों के प्रति सजगता दोनों दिखाई देती थीं। उनके लिए पत्रकारिता केवल समाचार देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के भीतर विचार और संवाद को जीवित रखने का माध्यम थी।

**उपलब्धियों से बड़ी थी उनकी पहचान**

कपूरचंदजी को अनेक सम्मान प्राप्त हुए, लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियाँ पुरस्कारों में नहीं थीं।

किसी विद्यार्थी की प्रगति, किसी संस्था का विकास, किसी लेखक का आत्मविश्वास और किसी व्यक्ति को सही समय पर दिया गया सही सुझाव—यही उनके जीवन की वास्तविक उपलब्धियाँ थीं।

उनकी पहचान पदों या सम्मानों से अधिक उनके काम से बनी। साहित्य, शिक्षा, समाजसेवा और मानवीय संबंधों के क्षेत्र में उन्होंने जो योगदान दिया, वही उनकी सबसे स्थायी पहचान है।

उनकी बातचीत में साहित्य था, जैन दर्शन था, असमिया भाषा और संस्कृति थी, सामाजिक सरोकार थे और सबसे बढ़कर संवाद की वह आत्मीयता थी, जो किसी भी संबंध को औपचारिक होने से बचाती थी।

कपूरचंदजी पाटनी का जाना एक व्यक्ति का जाना भर नहीं है। यह साहित्य, शिक्षा और समाज के उस आत्मीय अध्यय का विराम है, जिसकी स्मृति लंबे समय तक बनी रहेगी।

## संपादकीय

## वंदे मातरम् पर राजनीति

‘वंदे मातरम्’ केवल दो शब्द नहीं, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की स्मृतियों और राष्ट्रभावना से जुड़ा एक ऐतिहासिक उद्घोष है। लेकिन आज यही गीत राजनीतिक बहस और आरोप-प्रत्यारोप का विषय बनता जा रहा है। सवाल यह है कि क्या देशभक्ति भी अब राजनीतिक खेलों में बांटी जाएगी?

वंदे मातरम् गाने या न गाने को लेकर किसी नागरिक की निष्ठा पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक मर्यादा के अनुकूल नहीं है। देशभक्ति का प्रमाण किसी नारे की ऊंचाई से नहीं, बल्कि नागरिक के कर्म, जिम्मेदारी और संविधान के प्रति सम्मान से मिलता है। दूसरी ओर, इस गीत के ऐतिहासिक महत्व को कमतर आंकना भी उचित नहीं होगा। स्वतंत्रता आंदोलन में इसने करोड़ों भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जगाने का काम किया।

दुर्भाग्य यह है कि राजनीतिक दल इस संवेदनशील विषय को अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई इसे राष्ट्रवाद की कसौटी बना रहा है तो कोई इसके बहाने बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की राजनीति को हवा दे रहा है। इससे न गीत का सम्मान बढ़ता है, न देश मजबूत होता है।

जरूरत इस बात की है कि ‘वंदे मातरम्’ को राजनीतिक हथियार नहीं, राष्ट्रीय विरासत के रूप में देखा जाए। लोकतंत्र में सम्मान जरूरी है, लेकिन सम्मान थोपना नहीं जा सकता। देशभक्ति दिल से आती है, दबाव से नहीं।

आज राजनीति को तय करना होगा कि वह ‘वंदे मातरम्’ के नाम पर समाज को बांटेगी या इसके मूल संदेश-मातृभूमि के प्रति सम्मान और राष्ट्र के प्रति समर्पण-को आत्मसात करेगी। राष्ट्रीय और राष्ट्रभावना को चुनावी नारों की कैद से मुक्त करना ही सच्ची देशभक्ति है।

## काला पानी : जहां कैद हुई देह लेकिन आजादी की आवाज नहीं

अंडमान की सेलुलर जेल, जिसे ‘काला पानी’ कहा जाता है, ब्रिटिश शासन की उस क्रूर व्यवस्था का प्रतीक थी, जिसका उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों की आवाज को दबाना था। 1906 में पूरी हुई इस जेल में सात शाखाएं थीं और सैकड़ों एकांत कोठरियां, जहां कैदियों को मुख्य भूमि से दूर रखकर मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी जाती थीं।

कैदियों को नारियल का रेशा निकालने और तेल पेरने जैसे बेहद कठिन काम करवाए जाते थे। निर्धारित लक्ष्य पूरा न होने पर उन्हें कठोर दंड दिया जाता था। अकेलापन, भूख, निगरानी और अमानवीय व्यवहार उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। इसके बावजूद क्रांतिकारियों ने हार नहीं मानी। जेल में राजनीतिक कैदियों ने विरोध और भूख हड़ताल का रास्ता अपनाया। महावीर सिंह, मोहन किशोर नामदास और मोहित मोडन ने जबरन भोजन कराए जाने के दौरान प्राण गंवाए। उनके बलिदान ने देशभर में आक्रोश पैदा किया और राजनीतिक कैदियों के साथ हो रहे अत्याचारों का मुद्दा राष्ट्रीय चर्चा में आया। विनायक दामोदर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त और योगेंद्र शुक्ल जैसे स्वतंत्रता सेनानी भी यहां कैद रहे।

## उपलब्धियां-चुनौतियां

## जन जन विचार

...मंजु शर्मा

15 अगस्त 2026 को भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। 15 अगस्त 1947 को मिली आजादी के बाद यह देश अनेक उतार-चढ़ावों से गुजरते हुए आज दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और प्रभावशाली लोकतांत्रिक शक्तियों में अपनी जगह बना चुका है। इस वर्ष का स्वतंत्रता दिवस इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अब आजादी के 80वें समारोह से आगे बढ़ते हुए 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर देख रहा है। केंद्र सरकार के अनुसार, 2026 के स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे।

लेकिन स्वतंत्रता दिवस केवल उपलब्धियों का उत्सव नहीं है। यह आत्ममंथन का अवसर भी है। तिरंगा जब लाल किले की प्राचीर पर लहराता है, तब हमें यह भी पूछना चाहिए कि क्या स्वतंत्रता का वास्तविक लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाया है?

**अर्थव्यवस्था मजबूत, लेकिन असमानता बड़ी चुनौती**  
भारत की अर्थव्यवस्था ने पिछले दशकों में उल्लेखनीय प्रगति की है। विश्व बैंक भी भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करता है और 2047 तक उच्च-मध्यम आय वाले देश का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में भारत की प्रगति को रेखांकित करता है।

लेकिन आर्थिक विकास का सबसे बड़ा सवाल उसका समान वितरण है। एक तरफ महानगरों में आधुनिक बुनियादी ढांचा, डिजिटल सेवाएं और नई तकनीक तेजी से बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और किसानों की आय से जुड़े प्रश्न अब भी गंभीर हैं।

भारत के सामने चुनौती केवल तेज आर्थिक विकास की नहीं, बल्कि ऐसा विकास सुनिश्चित करने की है जिसमें गरीब, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, महिलाएं और युवा भी बराबर के भागीदार बनें।

## युवा भारत और रोजगार की चुनौती

भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी है। लेकिन यही ताकत तब चुनौती बन सकती है जब युवाओं को पर्याप्त रोजगार और कौशल के अवसर न मिलें।

आज लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं, सरकारी नौकरियों और सीमित अवसरों के पीछे भाग रहे हैं। दूसरी ओर उद्योगों को कुशल श्रमिकों की आवश्यकता है। इसका अर्थ है कि भारत को शिक्षा और रोजगार के बीच मौजूद दूरी को तेजी से कम करना होगा।

डिग्री से ज्यादा जरूरी रोजगार योग्य कौशल है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा, जैव-प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष जैसे नए क्षेत्रों में युवाओं के लिए बड़े अवसर पैदा किए जा सकते हैं।

## शिक्षा और स्वास्थ्य : आजादी की असली कसौटी

किसी भी देश की वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन केवल उसकी जीडीपी या सड़कों से नहीं किया जा सकता। सवाल यह है कि आम नागरिक को अच्छी शिक्षा और सस्ता तथा गुणवत्तापूर्ण इलाज कितना उपलब्ध है।

सरकारी और निजी शिक्षा के बीच बढ़ता अंतर, महंगी उच्च शिक्षा और निजी चिकित्सा की ऊंची लागत मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए बड़ी चिंता बन चुकी है। जब किसी परिवार की वर्षों की बचत एक गंभीर बीमारी के इलाज में समाप्त हो जाती है या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा परिवार की आर्थिक क्षमता से बाहर हो जाती है, तब विकास की तस्वीर अधूरी दिखाई देती है।

इसलिए आने वाले वर्षों में स्वास्थ्य और शिक्षा को केवल सरकारी योजनाओं का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय

प्राथमिकता बनाना होगा।

## सीमा सुरक्षा और बदलती भू-राजनीति

भारत की स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा आज भी सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव, पाकिस्तान से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियां और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बदलते सामरिक समीकरण भारत को लगातार सतर्क रहने के लिए मजबूर करते हैं।

अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत सड़क, संचार, हवाई संपर्क और सैन्य ढांचा केवल सुरक्षा का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकीकरण का भी हिस्सा है।

भारत को अपनी सैन्य शक्ति के साथ-साथ आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन और अत्याधुनिक तकनीक पर भी तेजी से आगे बढ़ना होगा।

## जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण

भारत के सामने एक और गंभीर चुनौती जलवायु परिवर्तन है। बाढ़, सूखा, अत्यधिक गर्मी, भूस्खलन और अनियमित वर्षा का असर कृषि, शहरों और गरीब आबादी पर विशेष रूप से पड़ता है।

पूर्वोत्तर भारत, हिमालयी क्षेत्र और तटीय इलाकों में जलवायु परिवर्तन की चुनौती और अधिक गंभीर हो सकती है। इसलिए विकास का मॉडल ऐसा होना चाहिए जिसमें सड़क और उद्योग के साथ नदियां, जंगल, जलस्रोत और जैव विविधता भी सुरक्षित रहें।

## लोकतंत्र की मजबूती भी जरूरी

भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था शामिल है। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक आबादी का देश होने के नाते भारत के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती अत्यंत महत्वपूर्ण है।

राजनीतिक मतभेद लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा हैं, लेकिन सामाजिक विभाजन, नफरत, गलत सूचना और संस्थाओं पर अविश्वास लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती बन सकते हैं। आज जरूरत ऐसे राजनीतिक वातावरण की है जिसमें विचारों की लड़ाई हो, लेकिन समाज की एकता कमजोर न हो।

## 2047 की ओर भारत की सबसे बड़ी परीक्षा

भारत अब 2047 की ओर देख रहा है-जब स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होंगे। लेकिन विकसित भारत का सपना केवल बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से पूरा नहीं होगा।

विकसित भारत का अर्थ होगा-  
हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले।  
हर नागरिक को सुलभ स्वास्थ्य सुविधा मिले।

युवाओं को सम्मानजनक रोजगार मिले।  
किसानों की आय और जीवन स्तर बेहतर हो।

महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक भागीदारी बढ़े।  
गांव और शहर के बीच विकास का अंतर घटे।

सीमाएं सुरक्षित हों।  
पर्यावरण सुरक्षित रहे।

लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत हों।  
विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

आजादी का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं  
1947 में भारत ने विदेशी शासन से राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल की थी। 2026 में स्वतंत्रता दिवस हमें यह याद दिलाता है कि अब लड़ाई गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, असमानता, सामाजिक विभाजन और पिछड़ेपन के खिलाफ है।

आजादी की अगली मंजिल केवल आर्थिक महाशक्ति बनना नहीं, बल्कि ऐसा भारत बनाना है जहां किसी गरीब को इलाज के लिए अपनी जमीन न बेचनी पड़े, किसी बच्चे की प्रतिभा पैसे के अभाव में न रुके और किसी युवा को अवसर की तलाश में अपना भविष्य अंधकारमय न दिखाई दे।



# एक इंच जमीन नहीं खोई, चीनी घुसपैठ पर सेना का दावा

जन जन विचार  
...नई दिल्ली

अरुणाचल प्रदेश में चीन की कथित 'धीमी घुसपैठ' को लेकर उठे सवाल को लेकर स्पष्ट और कड़ा संदेश दिया है। सेना के अनुसार, भारत ने अरुणाचल प्रदेश में कोई क्षेत्र नहीं खोया है और सीमा पर सभी भारतीय चौकियां पूरी तरह नियंत्रण में हैं। सेना ने चीन की ओर से किसी 'स्लो एन्क्रोचमेंट' की बात को भी खारिज किया है।

सेना के सूत्रों के मुताबिक, भारतीय सेना और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चीनी गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही हैं और किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। भारतीय पक्ष का संदेश साफ है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है तथा सीमा पर किसी भी तरह का दबाव या यथास्थिति बदलने की कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी।

## तक्सिंग को लेकर उठे गंभीर सवाल

सेना का यह बयान ऐसे समय आया है जब अपर सुबनसिरी जिले के तक्सिंग सेक्टर को लेकर पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल (पीपीए) की चार सदस्यीय फैक्ट-फाइंडिंग समिति ने गंभीर दावे किए हैं। समिति ने 10 जुलाई 2026 को तक्सिंग का दौरा किया और स्थानीय नेताओं, बुजुर्गों तथा रक्षा अधिकारियों एवं जवानों से बातचीत

की। समिति का दावा है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने कुछ निर्धारित भारतीय पेट्रोलिंग प्वाइंट तक भारतीय जवानों की पहुंच सीमित करने की कोशिश की है। समिति ने पारंपरिक चराई और शिकार क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की आवाजाही पर भी चिंता जताई है।

सबसे गंभीर दावा शोरा-5 पेट्रोलिंग प्वाइंट को लेकर किया गया है। पीपीए समिति के अनुसार, 2023 में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच यहां टकराव हुआ था। इसके बाद भारतीय जवान कथित तौर पर पीछे हटे और दोबारा वहां नहीं लौटे। समिति का दावा है कि बाद में पीएलए ने वहां मौजूद भारतीय निशान और प्रतीकात्मक ढांचे हटा दिए।

हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि ये पीपीए समिति के निष्कर्ष हैं, भारतीय सेना का आधिकारिक आकलन नहीं। सेना ने इन दावों के विपरीत कहा है कि भारत ने कोई क्षेत्र नहीं खोया है और सभी पोस्ट भारतीय नियंत्रण में हैं।

## सीमा पर 'सीजनल वैक्यूम' की चिंता

पीपीए समिति ने तक्सिंग, माजा और गालमो क्षेत्रों में मौसमी सैन्य गतिविधियों को भी चिंता का विषय बताया है। समिति के अनुसार, भारी बर्फबारी और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भारतीय गश्त कई अग्रिम क्षेत्रों में वर्ष के कुछ महीनों तक सीमित रहती है, जबकि चीनी गतिविधियां पूरे साल जारी रहने की बात कही गई है।



इसी आधार पर समिति ने सीमा पर संभावित 'सीजनल वैक्यूम' को दूर करने की जरूरत बताई है। सीमा क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय समुदायों के लिए भी यह अहम मुद्दा है, क्योंकि पारंपरिक चराई, याक पालन और आवाजाही से जुड़े क्षेत्रों तक पहुंच प्रभावित होने की शिकायतें सामने आई हैं।

## सड़क और संचार ढांचा भी अहम हथियार

सीमा सुरक्षा केवल सैनिकों और हथियारों से तय नहीं होती। दुर्गम अरुणाचल में सड़क, संचार, बिजली और हेलीपैड जैसे सुविधाएं भी रणनीतिक महत्व रखती हैं।

पीपीए समिति ने नाचो-तक्सिंग सीमा सड़क को तेजी से पूरा करने, गालमो-पोकोला मार्ग को प्राथमिकता देने तथा अग्रिम क्षेत्रों में हेलीपैड, स्थायी सैन्य ठिकाने, बिजली और दूरसंचार सुविधाएं मजबूत करने की मांग की है।

दरअसल, किसी भी सीमा क्षेत्र में मजबूत बुनियादी ढांचा सैनिकों की त्वरित आवाजाही, रसद आपूर्ति और निगरानी क्षमता को बढ़ाता है। यही कारण है कि भारत और चीन दोनों पिछले वर्षों में सीमा के

नजदीक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं।

## चीन के साथ सीमा पर सतर्कता जरूरी

अरुणाचल प्रदेश भारत-चीन सीमा के सबसे संवेदनशील हिस्सों में शामिल है। दुर्गम पहाड़, अत्यधिक ऊंचाई और कठिन मौसम यहां सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती हैं। दूसरी ओर, चीन ने सीमा के अपने हिस्से में सड़क और अन्य बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है।

सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के आमने-सामने आने की घटनाएं नहीं हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा का कई हिस्सों में स्पष्ट सीमांकन नहीं होने के कारण पेट्रोलिंग के दौरान टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे मामलों को दोनों देशों के बीच बने सैन्य और कूटनीतिक तंत्र के माध्यम से संभालने की कोशिश की जाती है।

चीन की ओर से भी सीमा की स्थिति को सामान्यतः स्थिर बताया हुआ संवाद जारी रखने की बात कही जाती रही है। लेकिन भारत के लिए असली चुनौती जमीन पर अपनी मौजूदगी और सीमा प्रभुत्व को लगातार मजबूत बनाए रखना है।

## इतिहास से मिलती है सतर्क रहने की सीख

अरुणाचल की सीमा पर चीन की गतिविधियों का इतिहास पुराना है। 1959 में लॉगजु क्षेत्र में चीनी सैनिकों और भारतीय सुरक्षा बलों के बीच टकराव हुआ था। 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान भी कामेंग, सुबनसिरी, सियांग और लोहित घाटियों में बड़े सैन्य

अभियान हुए थे।

इतिहास यह बताता है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी भी तरह की कमजोरी लंबे समय में गंभीर सुरक्षा चुनौती बन सकती है। इसलिए आज का सवाल केवल यह नहीं है कि किसी विशेष स्थान पर भारत ने जमीन खोई है या नहीं। बड़ा सवाल यह है कि सीमा पर भारत की निरंतर और प्रभावी मौजूदगी कितनी मजबूत है।

## चीन को स्पष्ट संदेश

भारतीय सेना का यह बयान कि 'भारत ने कोई क्षेत्र नहीं खोया है और सभी पोस्ट नियंत्रण में हैं', सीमा सुरक्षा को लेकर देश की स्थिति को स्पष्ट करता है। साथ ही यह भी संकेत देता है कि भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किसी भी एकतरफा बदलाव को स्वीकार नहीं करेगा।

अब आवश्यकता केवल दावों तक सीमित रहने की नहीं, बल्कि सीमा पर सड़क, पुल, सुरंग, हेलीपैड, संचार नेटवर्क और स्थायी सैन्य बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने की है। अग्रिम क्षेत्रों में सालभर निगरानी और प्रभावी उपस्थिति भी उतनी ही जरूरी है।

अरुणाचल प्रदेश की बर्फीली चोटियों पर भारत की मजबूत मौजूदगी ही सबसे बड़ा रणनीतिक संदेश है। चीन यदि दबाव, लगातार पेट्रोलिंग या बुनियादी ढांचे के जरिए जमीन पर नई स्थिति बनाने की कोशिश करता है, तो भारत की जवाबी क्षमता इतनी मजबूत होनी चाहिए कि ऐसी किसी भी कोशिश को शुरुआती चरण में ही रोक दिया जाए।

## पृष्ठ 1 का शेषांश...

## आजादी के जश्न...

भी कार्रवाई की। हमलों के बाद सोराब और ग्वादर समेत कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने सैन्य कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाते हुए नागरिकों की सुरक्षा और जवाबदेही की मांग की।

## जवाब में बीएलए के समन्वित हमले

हवाई कार्रवाई के बाद बलुच लिबरेशन आर्मी ने बलुचिस्तान के कई जिलों में पाकिस्तानी सुरक्षा प्रतिष्ठानों के खिलाफ हमले किए। चागाई, खुजदार, वाध, मंगुचर, झाओ और अन्य इलाकों से गोलीबारी, विस्फोट और सुरक्षा कafilों पर हमलों की खबरें सामने आईं।

चागाई में पुलिस स्टेशन पर बम हमले, यखनच में वाहनों पर घात लगाकर हमला, खुजदार के आरसीडी हाईवे पर सुरक्षा कafilों को निशाना बनाए जाने तथा वाध और मंगुचर में सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर हमलों

की रिपोर्ट है। हालांकि, विभिन्न घटनाओं में हताहतों और नुकसान से जुड़े दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

बीएलए ने इस महीने हुए अलग-अलग हमलों में पाकिस्तानी सैनिकों को बड़ी संख्या में मारने का दावा किया है। दूसरी ओर, पाकिस्तान का कहना है कि सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ों में कई उग्रवादियों को मार गिराया है। दोनों पक्षों के दावों के बीच वास्तविक स्थिति की स्वतंत्र पुष्टि मुश्किल बनी हुई है।

## दशकों पुराना असंतोष फिर सामने

बलुचिस्तान का संकट अचानक पैदा हुआ सुरक्षा संकट नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत प्राकृतिक गैस, खनिज और अन्य संसाधनों से समृद्ध है तथा इसकी रणनीतिक समुद्री स्थिति भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद स्थानीय आबादी का एक वर्ग लंबे समय से विकास, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और प्राकृतिक संसाधनों के लाभ में पर्याप्त हिस्सेदारी नहीं मिलने की शिकायत करता रहा है।

बलुच राष्ट्रवादी संगठनों का आरोप है

कि प्रांत की प्राकृतिक संपदा का लाभ स्थानीय लोगों की अपेक्षा केंद्र के सत्ता प्रतिष्ठान को अधिक मिलता है। वे राजनीतिक अधिकारों, संसाधनों पर स्थानीय नियंत्रण और आत्मनिर्णय की मांग भी उठाते रहे हैं।

## हिंसा का बढ़ता चक्र

बलुचिस्तान में मौजूदा घटनाक्रम को केवल अलग-अलग आतंकी हमलों या सैन्य कार्रवाइयों के रूप में देखना पूरे संकट की तस्वीर को अधूरा छोड़ देगा। यहां एक खतरनाक चक्र बनता दिखाई दे रहा है-सैन्य कार्रवाई, नागरिकों में आक्रोश, विद्रोही संगठनों की जवाबी हिंसा और फिर कठोर सुरक्षा अभियान।

इस चक्र ने आम नागरिकों के लिए स्थिति को और मुश्किल बना दिया है। एक तरफ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को विद्रोही हिंसा से निपटना है, तो दूसरी ओर नागरिक आबादी पर सैन्य कार्रवाई के आरोप बलुच असंतोष को और बढ़ाने की आशंका पैदा करते हैं।

## पाकिस्तान के सामने बड़ी चुनौती

बलुचिस्तान में स्वतंत्रता आंदोलन की

सफलता या वास्तविक राजनीतिक स्वतंत्रता की घोषणा को फिलहाल अंतिम निष्कर्ष मानना जल्दबाजी होगी। लेकिन यह जरूर स्पष्ट है कि दशकों के सैन्य अभियानों और दमन के आरोपों के बावजूद बलुच राष्ट्रवादी भावना समाप्त नहीं हुई है।

अब सवाल केवल सुरक्षा का नहीं, बल्कि राजनीतिक पहचान, संसाधनों पर अधिकार, मानवाधिकार और आत्मनिर्णय का भी है। पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि क्या वह इस लंबे संकट का समाधान केवल सैन्य शक्ति के माध्यम से कर सकता है या फिर राजनीतिक संवाद और स्थानीय आकांक्षाओं को जगह देकर कोई स्थायी रास्ता तलाशेगा।

बलुचिस्तान की मौजूदा हिंसा यह संकेत देती है कि जिस मुद्दे को लंबे समय तक महज कानून-व्यवस्था की समस्या मानकर देखा गया, वह अब पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति और क्षेत्रीय भू-राजनीति के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है।

# युवा क्रांतिकारी शहीद खुदीराम बोस

— जन जन विचार —



... डॉ. मुकेश कुमार

भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास केवल तिथियों, लड़ाइयों और राजनीतिक समझौतों की सूची मात्र नहीं है; यह उन अनगिनत आत्माओं के त्याग और स्मरण से लिखा गया महाकाव्य है, जिन्होंने देश की वेदी पर अपने प्राण न्योछावर कर दिए। जब भी बीसवीं सदी के शुरुआती दौर के उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन और सशस्त्र क्रांति की चर्चा होती है, तो एक किशोरीय मुस्कान और बुलंद होंसले का चित्र मानस पटल पर उभरता है, वह चित्र है अमर शहीद खुदीराम बोस का। 11 अगस्त 1908 की अल सुबह मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में जब मात्र 18 वर्ष, 8 महीने और 8 दिन की अवस्था में यह नवयुवक हाथ में श्रीमद्भगवद्गीता लेकर हंसते-हंसते फांसी के फंदे पर झूल गया, तो उसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी।

जमानास में अक्सर यह धारणा देखने को मिलती है कि खुदीराम बोस भारत की आजादी के लिए फांसी चढ़ने वाले 'सर्वप्रथम' सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे। यद्यपि ऐतिहासिक प्रामाणिकता के संदर्भ में देखा जाए तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम (1857 के संग्राम) के दौरान मंगल पांडे, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के सहयोगी और असम के मणिमर दीवान जैसे वीरों को फांसी या शहादत प्राप्त हो चुकी थी। 1857 के पश्चात भी 1897 में पुणे के चापेकर बंधुओं (दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव) को रैंड हत्याकांड के लिए फांसी दी जा चुकी थी। इसके अतिरिक्त, महान इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार की पुस्तक 'हिस्ट्री ऑफ द प्रोडम मूवमेंट इन इंडिया' (खंड 2) में इस बात का स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि बीसवीं शताब्दी में बंगाल के उग्र क्रांतिकारी पुनःस्थापन के दौर में ब्रिटिश न्याय व्यवस्था द्वारा फांसी के फंदे पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के और पहले प्रमुख क्रांतिकारियों में खुदीराम बोस का नाम अग्रणी है। वे बीसवीं सदी के भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के उस 'युगांतर' अध्याय के प्रथम महानायक बने, जिसने भारत के युवाओं में शहादत का एक नया जन्म पैदा किया। हिंदी

की चांद पत्रिका के फांसी विशेषांक में लिखा है — 'भारतीय स्वाधीनता के संघर्ष में बीसवीं शताब्दी के आरंभ में ही ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध काम करने वाले क्रांतिकारी के लिए मृत्यु-दंड का जो सिलसिला खुदीराम बोस ने शुरू किया था, वह भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दिए जाने के साथ और तेजी के साथ चलता रहा।'

3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के हबीबपुर गांव में जन्मे खुदीराम बोस के बचपन से ही क्रांति के प्रति गहरे अनुराग का पता चलता है। माता लक्ष्मीप्रिया देवी और पिता त्रैलोक्यनाथ बोस के निधन के बाद उनका लालन-पालन उनकी बड़ी बहन अपरूपा देवी ने किया। तत्कालीन ब्रिटिश अभिलेखों और मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस के अदालती दस्तावेजों से ज्ञात होता है कि किशोरावस्था में ही खुदीराम बोस 'अनुशीलन समिति' और 'युगांतर' जैसी क्रांतिकारी संस्थाओं के संपर्क में आ चुके थे। वे श्री अरविंद और बारिंद कुमार घोष के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। सन 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की, तो पूरे बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की ज्वाला भड़क उठी। 1906 में मेदिनीपुर में आयोजित एक औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी के दौरान खुदीराम बोस को अंग्रेजी शासन के खिलाफ भड़काऊ पर्चे (सोनार बांग्ला) बांटते हुए पहली बार गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया था, परंतु वे सिपाही को चकमा देकर भागने में सफल रहे। यह घटना उनके अडिग संकल्प की प्रथम प्रामाणिक गवाही देती है।

उस दौर में कलकत्ता (अब कोलकाता) का मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड अपने क्रूर और पक्षपातपूर्ण फैसलों के लिए भारतीयों के बीच कुख्यात था। उसने स्वदेशी आंदोलनकारियों, विशेषकर युवा सत्याग्रहियों को कोड़े मारने और कठोर शारीरिक यातनाएं देने का सिलसिला चला रखा था। 1907 में जब 'युगांतर' पत्रिका के संपादक भूपेंद्रनाथ दत्त पर राजद्रोह का मुकदमा चला और उसके विरोध में एकत्रित जनता पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तब सुशील सेन नामक एक 15 वर्षीय बालक ने विरोध जताया। किंग्सफोर्ड ने उस बालक को खुलेआम 15 कोड़े मारने का आमानवीय सजा सुनाई। इस घटना ने क्रांतिकारी दल को उद्बेलित कर दिया। क्रांतिकारी गुप्त समिति ने किंग्सफोर्ड को मृत्युदंड देने का निर्णय

लिया। ब्रिटिश सरकार को जब किंग्सफोर्ड पर संभावित हमले की भनक लगी, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसका पदोन्नति के साथ स्थानांतरण मुजफ्फरपुर (बिहार) के जिला जज के रूप में कर दिया गया।

युगांतर दल के नेतृत्व ने किंग्सफोर्ड का पीछा मुजफ्फरपुर तक करने की योजना बनाई। इस साहसिक और जोखिम भरे कार्य का दायित्व दो नवयुवकों, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी को सौंपा गया। मुजफ्फरपुर पहुंचकर दोनों क्रांतिकारियों ने छद्म नाम (दिनेश चंद्र रॉय और हरेन सरकार) धारण किए और 'किशोर क्लब' में ठहरकर कई दिनों तक किंग्सफोर्ड की दिनचर्या, उसके वाहन और कोर्ट आने-जाने के समय की बारीक रोक की।

30 अप्रैल 1908 की शाम, भारतीय स्वाधीनता संग्राम का एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुई। मुजफ्फरपुर के यूरोपियन क्लब के बाहर खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी घात लगाकर बैठ गए। रात लगभग 8.30 बजे जैसे ही किंग्सफोर्ड के आवास की ओर एक बग्गी आती हुई दिखाई दी, दोनों ने उसे किंग्सफोर्ड की गाड़ी समझकर उस पर बम फेंक दिया। भयानक धमाके के साथ बग्गी क्षतिग्रस्त हो गई। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था; उस बग्गी में किंग्सफोर्ड मौजूद नहीं था, बल्कि उसमें दो ब्रिटिश महिलाएं जिनमें क्लीवलैंड केनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री सवार थीं, जिनकी इस हमले में मृत्यु हो गई।

घटना के उपरांत दोनों क्रांतिकारी अलग-अलग दिशाओं में नंगे पांव भाग निकले। प्रफुल्ल चाकी समस्तीपुर की ओर बढ़े, जहां बाद में मोकामा स्टेशन पर पुलिस से घिर जाने पर उन्होंने अंग्रेजों की गिरफ्त में आने के बजाय स्वयं को गोली मारकर शहादत चुन ली। दूसरी ओर, खुदीराम बोस पूरी रात बिना अन्न-जल के लगभग 25 मील की दूरी तय करके बैनी रेलवे स्टेशन (जो अब 'खुदीराम बोस युवा स्टेशन' के नाम से जाना जाता है) पहुंचे। 1 मई 1908 की सुबह जब वे एक दुकान पर पानी पी रहे थे और वहां चल रही बमकांड की चर्चा सुन रहे थे, तभी दो पुलिस कांस्टेबलों को उन पर संदेह हुआ। तलाशी लेने पर उनके पास से दो रिवॉल्वर, 37 कारतूस और 30 रुपए नकद बरामद हुए। खुदीराम को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया।

मुजफ्फरपुर बमकांड का यह

मामला पूरे देश में आग की तरह फैल गया। तत्कालीन ब्रिटिश समाचार पत्रों जैसे 'द स्टेट्समैन' और 'दि एम्पायर' ने 2 मई 1908 के अपने अंकों में खुदीराम की गिरफ्तारी की खबर को प्रमुखता से छापा। 'द स्टेट्समैन' ने लिखा था कि जब 18 वर्षीय लड़के को हथकड़ियों में जकड़कर स्टेशन लाया जा रहा था, तब भी उसके चेहरे पर भय की एक रेखा तक नहीं थी; वह पूर्णतः शांत और निर्भीक दिख रहा था।

21 मई 1908 को मुजफ्फरपुर की विशेष अदालत में जज कॉर्नडफ की अदालत में ट्रायल शुरू हुआ, जिसे 'मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस' (Case No. 11 of 1908) के नाम से जाना जाता है। खुदीराम की ओर से पैरवी के लिए वकीलों की एक टीम आगे आई, जिसमें उषेन्द्रनाथ सेन और कालिदास बसु जैसे प्रख्यात बैरिस्टर शामिल थे। अदालती दस्तावेजों के अनुसार, जब जज ने खुदीराम से पूछा कि 'क्या तुम जानते हो कि बम फेंकने का परिणाम क्या होता है?', तो इस वीर बालक ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया था, 'यदि आप मुझे थोड़ा समय दें, तो मैं आपको बम बनाना भी सिखा सकता हूं।' 13 जुलाई 1908 को अदालत ने खुदीराम बोस को मौत की सजा (फांसी) सुनाई (चांद, फांसी अंक)।

जब जज ने फांसी का फैसला पढ़कर सुनाया, तो खुदीराम के चेहरे पर एक मंद मुस्कान तैर गई। जज ने हैरान होकर पूछा कि क्या उन्हें समझ आया है कि उन्हें मृत्युदंड दिया गया है? खुदीराम ने निडरता से कहा कि वे पूरी तरह समझ चुके हैं। फांसी की सजा के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई, परंतु 13 जुलाई 1908 को ही हाई कोर्ट के जज ब्रेट और रयान ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।

11 अगस्त 1908 की सुबह मुजफ्फरपुर जेल में फांसी की तैयारी की गई। 'अमृत बाजार पत्रिका' के 12 अगस्त 1908 के अंक में इस फांसी का आंखों देखा जीवंत विवरण प्रकाशित हुआ था। समाचार पत्र के अनुसार, खुदीराम फांसी के तख्ते की ओर ऐसे बढ़े जैसे कोई बालक खेल के मैदान की ओर बढ़ता है। उनके एक हाथ में श्रीमद्भगवद्गीता थी और हाथों पर 'वंदे मातरम' का उद्घोष था। जब फांसी का फंदा उनके गले में डाला गया, तब भी उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उन्होंने

स्वयं हंसते हुए फंदे को सही स्थान पर बैठाया।

खुदीराम बोस की इस शहादत ने पूरे भारत, विशेषकर बंगाल के युवाओं के भीतर देशभक्ति की एक प्रचंड लहर पैदा कर दी। उस दौर में बंगाली जुलाहों ने एक विशेष प्रकार की धोती बुनना शुरू किया था, जिसके किनारे पर अंग्रेजी में 'खुदीराम' लिखा होता था। बंगाल के नौजवान इस 'खुदीराम धोती' को पहनकर गर्व महसूस करते थे। लोकगायक पीतांबर दास द्वारा रचित प्रसिद्ध बंगाली लोकगीत 'एक बार बिदाय दे मा धूरे आसी' (मुझे एक बार बिदा दो मां, मैं फिर वापस आऊंगा) घर-घर में गूँजने लगा, जो खुदीराम बोस की अमर भावना को समर्पित था।

महान स्वतंत्रता सेनानी और बाल गंगाधर तिलक ने अपने समाचार पत्र 'केसरी' में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के साहस की सराहना करते हुए लेख लिखे थे, जिसके कारण तिलक जी पर भी राजद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें लोकोपाल जेल भेज दिया गया था। लोकमान्य तिलक ने लिखा था कि यह हमला केवल दो व्यक्तियों का नहीं था, बल्कि यह औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ भारत की युवा चेतना का एक स्वतःस्फूर्त विस्फोट था।

खुदीराम बोस का जीवन भले ही केवल 18 वर्षों का अल्प जीवनकाल रहा हो, लेकिन उनका त्याग किसी भी दीर्घकालिक राजनीतिक जीवन से कहीं अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुआ। वे भारत के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में उस अमर ज्योति की तरह स्थापित हुए, जिसने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और चंद्रशेखर आजाद जैसे भावी क्रांतिकारियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। मुजफ्फरपुर जेल के उस फांसी के तख्ते ने एक किशोर के शरीर को भले ही निष्प्राण कर दिया हो, लेकिन खुदीराम बोस की आत्मा भारत की आजादी के संघर्ष में हमेशा के लिए अमर हो गई। प्रामाणिक दस्तावेज, अदालती रिकार्ड और तत्कालीन समकालीन समाचार पत्र इस बात के अमिट साक्ष्य हैं कि खुदीराम बोस बीसवीं सदी के भारत के सबसे कम उम्र के प्रथम फांसी पाने वाले उन महानायकों में से थे, जिनकी शहादत ने ब्रिटिश हुकूमत के पतन की उल्टी गिनती शुरू कर दी थी और भारत को 15 अगस्त सन् 1947 ई को आजादी मिली। ऐसे महान अमर क्रांतिकारी योद्धाओं के हम सदैव ऋणी रहेंगे।



# गॉल में श्रीलंकाई स्पिन के चक्रव्यूह की चुनौती

जन जन विचार  
...गॉल

श्रीलंका के गॉल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला सिर्फ दो टीमों की टक्कर नहीं, बल्कि भारतीय बल्लेबाजों और श्रीलंकाई स्पिन के बीच एक दिलचस्प रणनीतिक जंग भी बनने जा रहा है। गॉल की पिच और परिस्थितियाँ स्पिन गेंदबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती हैं और ऐसे में श्रीलंका के प्रभात जयसूर्या तथा रमेश मैडिस भारतीय बल्लेबाजी क्रम के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर सकते हैं।

गॉल को प्रभात जयसूर्या और रमेश मैडिस ने लगभग अपना घरेलू किला बना लिया है। दोनों गेंदबाजों ने इस मैदान पर लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, दोनों ने मिलकर गॉल में 145 विकेट हासिल किए हैं। जयसूर्या ने केवल 11 टेस्ट में 81 विकेट लेकर अपनी उपयोगिता साबित की है, जबकि रमेश मैडिस ने 12 टेस्ट में 64 विकेट अपने नाम किए हैं।

**'किंग ऑफ गॉल' जयसूर्या पर नजर**

श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर फरवेज महरूफ ने प्रभात जयसूर्या को श्रीलंका का सबसे बड़ा हथियार बताते हुए उन्हें 'किंग ऑफ गॉल' कहा है। इसकी वजह भी स्पष्ट है। जयसूर्या को गॉल की परिस्थितियों का बेहतरीन ज्ञान है और वह हवा का इस्तेमाल करते हुए गेंद को बल्लेबाज के लिए और अधिक चुनौतीपूर्ण बना देते हैं।

उनकी गेंदबाजी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सटीक लाइन और लेथ है। वह बल्लेबाज को खुलकर शॉट खेलने का अवसर नहीं देते। इसके अलावा उनकी अंडर-कटर और आर्म बॉल जैसी गेंदें बल्लेबाजों को भ्रमित करने में सक्षम हैं। यदि पिच पर असमान उछाल मौजूद रहा तो जयसूर्या की सटीक



श्रीलंका के गॉल में पहले टेस्ट मैच से पूर्व अभ्यास सत्र के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल।

गेंदबाजी और भी खतरनाक हो सकती है।

पूर्व श्रीलंकाई स्पिनर उणुल चंदना के अनुसार, जयसूर्या बहुत कम समय में श्रीलंका के प्रमुख स्पिन हथियार बन गए हैं। उनके खिलाफ केवल रक्षात्मक रवैया अपनाना बल्लेबाजों के लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि इससे गेंदबाज को लगातार दबाव बनाए रखने का मौका मिलता है।

**दूसरे छोर से मैडिस का दबाव**

जयसूर्या की चुनौती अकेले नहीं होगी। दूसरे छोर से रमेश मैडिस भारतीय बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रख सकते हैं। ऑफ स्पिनर मैडिस विशेष रूप से बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए परेशानी खड़ी करने की क्षमता रखते हैं। वह अलग कोण से गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज को अपनी पसंद के शॉट खेलने से रोकने की कोशिश करते हैं।

यही कारण है कि भारत के शीर्ष क्रम के लिए यह मुकाबला विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा। भारतीय टीम में यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत जैसे आक्रामक बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। दोनों अगर शुरुआती ओवरों में श्रीलंकाई स्पिन के जाल में फंसेते हैं तो भारत पर दबाव तेजी से बढ़ सकता है।

**यशस्वी और पंत के लिए अग्निकालीय**

यशस्वी जायसवाल आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। वह गेंदबाज पर दबाव बनाने और रन गति बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन गॉल जैसी परिस्थितियों में आक्रामकता और धैर्य के बीच संतुलन बेहद जरूरी होगा। जयसूर्या की अंडर-कटर गेंदों और मैडिस की ऑफ स्पिन के सामने यशस्वी को अपने फुटवर्क और शॉट चयन पर विशेष ध्यान देना होगा।

ऋषभ पंत के लिए चुनौती थोड़ी अलग होगी। वह स्वाभाविक रूप से आक्रामक बल्लेबाज हैं और स्पिन के खिलाफ बड़े शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं। लेकिन गॉल में हवा, टर्न और असमान उछाल उनके लिए जोखिम भी पैदा कर सकते हैं। पंत को यह तय करना होगा कि कब गेंदबाज पर हमला करना है और कब धैर्य के साथ गेंद को छोड़ना या रोकना है।

**भारत की रणनीति क्या होगी?**

भारत के लिए सबसे जरूरी होगा कि वह श्रीलंकाई स्पिनरों को शुरुआत से ही लय हासिल न करने दे केवल रक्षात्मक बल्लेबाजी करने से समस्या बढ़ सकती है। भारतीय बल्लेबाजों को स्ट्राइक बदलने, गेंदबाजों की लंबाई बिगाड़ने और सही समय पर आक्रमण करने की रणनीति अपनानी होगी।

गॉल में पिच के साथ-साथ हवा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए भारतीय बल्लेबाजों को गेंद की गति, टर्न और हवा के प्रभाव को लगातार पढ़ना होगा। शुरुआती चरण में विकेट बचाकर रचना और बाद में रन गति बढ़ाना भारत के लिए उपयोगी रणनीति हो सकती है।

**गॉल की पिच भी बनेगी निर्णायक**

मैच से पहले मध्य पिच पर पानी डाले जाने से बल्लेबाजी के लिए अपेक्षाकृत बेहतर विकेट की उम्मीद जरूर बनी है। लेकिन टेस्ट मैच आगे बढ़ने के साथ पिच का व्यवहार बदल सकता है। जैसे-जैसे सतह सूखेगी, स्पिनरों को अधिक मदद मिलने की संभावना बढ़ सकती है।

यही वह स्थिति होगी जहां जयसूर्या और मैडिस की जोड़ी भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। एक छोर से बाएं हाथ की स्पिन और दूसरे छोर से ऑफ स्पिन भारतीय बल्लेबाजों की तकनीक और धैर्य दोनों की परीक्षा लेगी।

## पृष्ठ 1 का शेषांश...

### बलूचिस्तान आजाद!

हालांकि, महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने बलूचिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की कोई घोषणा नहीं की है। बलूच नेतृत्व भारत के व्यापक मानवाधिकार संबंधी रुख को अपने आंदोलन के समर्थन के संकेत के रूप में प्रस्तुत कर रहा है।

### 11 अगस्त की तारीख को बताया ऐतिहासिक आधार

बलूच नेतृत्व का दावा है कि ब्रिटिश शासन समाप्त होने और भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन से ठीक पहले 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। इसी दावे को आधार बनाकर वर्तमान आंदोलन को स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय

मान्यता की लड़ाई के रूप में पेश किया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस दावे को मान्यता नहीं देते तथा बलूचिस्तान को पाकिस्तान का प्रांत माना जाता है।

बलूच नेतृत्व अब अपने आंदोलन को केवल सड़क और राजनीतिक विरोध तक सीमित रखने के बजाय अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र, आसियान, अफ्रीकी संघ, इस्लामिक सहयोग संगठन और यूरोपीय देशों से बलूचिस्तान के पक्ष में आवाज उठाने की अपील की गई है।

**स्वतंत्र राष्ट्र की तैयारी का दावा**

बलूच समूहों की ओर से दावा किया गया है कि भविष्य के स्वतंत्र राष्ट्र के लिए विदेश नीति, रक्षा, अर्थव्यवस्था, शासन और कूटनीति से संबंधित ढांचे तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा अलग मुद्रा,

पासपोर्ट, मीडिया संस्थानों, व्यापारिक संगठनों तथा विदेशों में राजनयिक मिशनों की तैयारी का भी दावा किया गया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

बलूच नेतृत्व पाकिस्तान पर जबरन गुमशुदगी, हिरासत, लश्कृत हत्याओं और मानवाधिकार उल्लंघनों के गंभीर आरोप लगाता रहा है। उसका दावा है कि बड़ी संख्या में बलूच लोग हिरासत और दमन का सामना कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस से जुड़े कार्यक्रमों को रोकने के लिए इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं पर प्रतिबंध तथा सुरक्षा बलों की भारी तैनाती के भी आरोप लगाए गए हैं।

**पाकिस्तान के लिए क्यों अहम**

**है बलूचिस्तान?**

रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्षेत्रफल के

लिहाज से यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध माना जाता है। इसका भौगोलिक स्थिति भी इसे अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है। लंबे समय से जारी बलूच विद्रोह और स्वतंत्रता की मांग पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा के साथ-साथ क्षेत्रीय भू-राजनीति का भी अहम विषय बन चुके हैं।

भारत के संदर्भ में बलूचिस्तान का मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान लंबे समय से जम्मू-कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है। बलूच नेतृत्व द्वारा भारत के बयानों और मीडिया कवरेज को अपने पक्ष में प्रचारित करना पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

**संघर्ष अब कूटनीतिक मोर्चे पर**  
बलूचिस्तान का संघर्ष अब केवल अलगाववादी समूहों और

पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच सशस्त्र टकराव तक सीमित नहीं दिख रहा। यह इतिहास, मानवाधिकार, प्राकृतिक संसाधनों, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और सूचना युद्ध के कई मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है।

भारत के प्रति बलूच नेतृत्व का सार्वजनिक आभार इस बदलते रणनीतिक समीकरण की ओर संकेत करता है। हालांकि नई दिल्ली ने अभी तक बलूचिस्तान की स्वतंत्रता या 'रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान' को मान्यता देने के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। ऐसे में आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि बलूच आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना समर्थन मिलता है और भारत-पाकिस्तान संबंधों के व्यापक संदर्भ में यह मुद्दा किस दिशा में आगे बढ़ता है।

# बापू पर पत्थरों की बौछार, अस्सलाम आलेकुम के साथ जन्मा पाकिस्तान

15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र होने वाला था। देश आजादी की दहलीज पर खड़ा था, लेकिन वातावरण में उत्सव से कहीं अधिक बेचैनी, हिंसा और विभाजन की पीड़ा थी। 13 अगस्त का दिन इस उथल-पुथल भरे दौर की कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी बना। एक ओर महात्मा गांधी सांप्रदायिक हिंसा के बीच शांति स्थापित करने के प्रयास में जुटे थे, तो दूसरी ओर सत्ता हस्तांतरण और विभाजन से जुड़े फैसले उपमहाद्वीप का भविष्य तय कर रहे थे।

## गांधी पर बरसे पत्थर और बोलतें

13 अगस्त को महात्मा गांधी कोलकाता के बेलियाघाटा स्थित हैदरी मंजिल पहुंचे। उनका उद्देश्य हिंदू-मुस्लिम तनाव के बीच शांति कायम करना था। गांधी के वहां पहुंचते ही कुछ लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। विरोध बढ़ा तो पत्थर और बोलतें भी फेंकी जाने लगीं।

गांधी ने स्थिति का सामना आक्रोश से नहीं, बल्कि शांति और संवाद से किया। उन्होंने भीड़ के सामने आकर लोगों को शांत रहने का आग्रह किया। इसके बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि वे हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की सेवा के लिए वहां आए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि कोलकाता में रहने वाले मुस्लिम नागरिकों को सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

गांधी का यह रवैया उस समय उनके शांति अभियान की मूल भावना को दर्शाता था। देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा भड़क रही थी, लेकिन गांधी हिंसा का जवाब हिंसा से देने के बजाय लोगों के विवेक को जगाने में विश्वास रखते थे।

## उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत का सवाल

विभाजन के समय उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत (एनडब्ल्यूएफपी), जिसे आज मुख्यतः खैबर पख्तूनख्वा के नाम से जाना जाता है, का भविष्य भी महत्वपूर्ण विवाद का विषय था। यहां कांग्रेस समर्थित नेतृत्व का प्रभाव था और खान अब्दुल गफ्फार खान तथा उनके अनुयायियों ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान योजना का विरोध किया था।

यहां यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस प्रांत का पाकिस्तान में जाना केवल किसी एक नेता की 'जिद' का परिणाम बताना ऐतिहासिक रूप से अत्यधिक सरलीकरण होगा। ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस नेतृत्व के बीच इसके भविष्य को लेकर मतभेद थे। अंततः जून-जुलाई 1947 में हुए जनमत-संग्रह के माध्यम से भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दिया गया। कांग्रेस और खुदाई खिदमतगारों ने इस प्रक्रिया का बहिष्कार किया। मतदान में पाकिस्तान के पक्ष में भारी बहुमत आया और प्रांत पाकिस्तान में

शामिल हो गया।

यह फैसला खान अब्दुल गफ्फार खान और उनके समर्थकों के लिए गहरा आघात था। उनका मानना था कि पश्तूनों को अपनी राजनीतिक इच्छा के अनुसार अधिक व्यापक विकल्प मिलना चाहिए था। विभाजन की प्रक्रिया में उनकी उपेक्षा ने बाद के दशकों में भी इस क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित किया।

## लाहौर से बदली रेडियो की आवाज

आजादी और विभाजन का असर संचार माध्यमों पर भी दिखाई दे रहा था। लाहौर स्थित रेडियो केंद्र ब्रिटिश भारत की प्रसारण व्यवस्था का हिस्सा था, लेकिन सत्ता हस्तांतरण के साथ उसकी भूमिका बदलने वाली थी।

14 अगस्त को मध्यरात्रि के आसपास लाहौर से पाकिस्तान की नई प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई। 'अस्सलाम आलेकुम' के अभिवादन के साथ श्रोताओं का पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में स्वागत किया गया। यह प्रसारण केवल रेडियो की आवाज में बदलाव नहीं था, बल्कि सत्ता और राजनीतिक भूगोल के एक बड़े परिवर्तन का प्रतीक था।

लाहौर, जो कभी अविभाजित भारत के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण केंद्र था, अब पाकिस्तान का हिस्सा बनने जा रहा था। रेडियो की बदली हुई आवाज ने इस परिवर्तन को आम लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

## आजादी के साथ बंटवारे का दर्द

13 अगस्त 1947 की घटनाएं यह याद दिलाती हैं कि भारत की स्वतंत्रता केवल उत्सव का क्षण नहीं थी। उसके साथ विभाजन की त्रासदी, सांप्रदायिक हिंसा, विस्थापन और लाखों लोगों की अनिश्चितता भी जुड़ी हुई थी।

एक तरफ दिल्ली में स्वतंत्र भारत की नई व्यवस्था आकार ले रही थी, दूसरी तरफ गांधी कोलकाता में हिंसा रोकने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कहीं सीमाओं का निर्धारण हो रहा था, तो कहीं लोगों को यह तय करना पड़ रहा था कि उनका घर अब किस देश में रहेगा। 13 अगस्त की कहानी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्वतंत्रता की पूर्व संध्या की वास्तविक तस्वीर सामने रखती है—एक ऐसा भारत जो आजादी के बेहद करीब था, लेकिन विभाजन के घावों से भी गहराई से घायल था। महात्मा गांधी की शांति की अपील, एनडब्ल्यूएफपी जैसे क्षेत्रों का राजनीतिक संघर्ष और लाहौर से बदली रेडियो आवाज—ये सभी घटनाएं मिलकर उस ऐतिहासिक दौर की जटिलता को समझने में मदद करती हैं। 15 अगस्त की सुबह स्वतंत्रता का सूरज जरूर उगा, लेकिन उसके साथ उपमहाद्वीप के इतिहास में एक ऐसी रेखा भी खिंच गई, जिसने भारत और पाकिस्तान के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया।

## एक गीत पंद्रह अगस्त की शान में

भारत में निकला सूर्य आज मस्त मस्त है  
वो खुश है आया आज पंद्रह अगस्त है

इस देश में जन्मा हर एक तन हर एक मन  
हर एक भारतीय यहां ओढ़ के कफन  
आजादी पे मिटने के लिए अभ्यस्त है  
वो खुश है आया आज पंद्रह अगस्त है

दुश्मन हो कोई भी गवाह आज का है दिन  
हम लड़ते रहे उससे बिना खौफ डरे बिन  
हमसे जो लड़ता है वही पाता सिद्धांत है  
वो खुश है आया आज पंद्रह अगस्त है

हर भूख प्यास दर्द घुटन कारवाह के भी  
बारिश में सदी गर्मी में खुले में रह के भी  
होता न कोई भारतीय कभी भी पस्त है  
वो खुश है आया आज पंद्रह अगस्त है

है याद आ रही हमें अनमोल वो घड़ी  
पाई थी हमने एक सफलता बहुत बड़ी  
था आज हुआ राज्य ए अंग्रेज अस्त है  
वो खुश है आया आज पंद्रह अगस्त है

बच्चे बूढ़े नौजवां मां बहनें बेटियां  
ले कर के तिरंगा चले बना के टोलियां  
आज की खुशी में तो हर एक व्यस्त है  
वो खुश है आया आज पंद्रह अगस्त है

है राज हमें नाज उन शहीदों पे सदा  
लिखते रहेंगे उनके हमेशा ही कुछ नया  
भागा था आतताई जिनसे हो के त्रस्त है  
वो खुश है आया आज पंद्रह अगस्त है

गजलराज

+919354091150

## नए अंदाज में मनायेंगे

इस बार स्वतंत्रता दिवस

नए अंदाज में मनाएंगे

स्वच्छ भारत बनाएंगे

गरीबों को मिटाएंगे

प्रदूषण हटाएंगे

पर्यावरण को बचाएंगे

स्वच्छ भारत हम बनाएंगे।

कूड़े-कचरे सहित गंदी सोच को

समूल मिटाएंगे

भारत का नया रूप

विश्व को दिखाएंगे।

प्लास्टिक को समूल मिटाएंगे

कपड़े के थैले अपनाएंगे

बच्चे, बूढ़े, जवान सभी

मिलकर नया भारत बनाएंगे

विश्व में भारत की

शान बढ़ाएंगे

हर बुराई को मिटाएंगे

सोचें अपनी सकारात्मक बना

हम बच्चे भारत को महकाएंगे

कुछ अलग अंदाज में

इस बार स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे।

पर्यावरण को बचाएंगे

स्वच्छ भारत बनाएंगे

वन्य जीव जंतुओं को

उनका आवास लौटाएंगे

बिजली पानी बचाएंगे।

स्वच्छ भारत बनाएंगे।

पेड़ पौधे लगाएंगे

धरती को संवारेंगे

हरी भरी वसुंधरा को

फिर से बनाएंगे

स्वच्छ भारत का सपना

अब हम सफल कर दिखाएंगे

स्वच्छ भारत बनाएंगे

तमाम बुराइयों को

समूल मिटाएंगे

पर्यावरण को स्वच्छ कर

नया भारत बनाएंगे

कूड़ा कचरा सहित

गंदी सोच को मिटाएंगे

हम भारतवासी अब नया

भारत बनाएंगे

स्वच्छ परिवेश, स्वच्छ पर्यावरण

सहित स्वच्छ मानसिकता को

ससम्मान अपनाएंगे

इस बार स्वतंत्रता दिवस

नए अंदाज में मनाएंगे।

देश सेवा का व्रत सदा निभाएंगे।

जय भारत जय हिंद

रजनी शर्मा दाधिच

गुवाहाटी



## देश के लिए

365 दिनों में एक दिन

देश के लिए निकालो,

365 दिनों में एक दिन

देश के लिए निकालो।

जो देश के लिए शहीद हुए,

उनको भी एक दिन नमन कर लो।

बड़ी-बड़ी बातों में

क्या रखा है ?

मातृभूमि के लिए

थोड़ा त्याग तो कर लो।

वैसे तो सब व्यस्त हैं,

किसी के पास समय नहीं।

तिरंगा जो हमारी जान है,

उसे फहराने के लिए

थोड़ा वक्त तो निकालो।

भारत माता की जय,

जय हिंद, वंदे मातरम्

बोलने के लिए

कुछ पल भी निकालो।

गोविंद कुमार विश्वास

गुवाहाटी, असम



## নগাঁও উপ-নিৰ্বাচনত এআইইডিএফৰ প্ৰাৰ্থী ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰ

গুৱাহাটী: নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ আগন্তুক উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে সৰ্বভাৰতীয় সংযুক্ত গণতান্ত্ৰিক মৰ্চা (এআইইডিএফ)-এ ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰক দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। দলটোৱে কংগ্ৰেছৰ সৈতে কোনো নিৰ্বাচনী মিত্ৰতা নকৰাৰ কথাও স্পষ্ট কৰি উপ-নিৰ্বাচনত স্বতন্ত্ৰভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে।

দলৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলে কংগ্ৰেছক অসম আৰু দেশৰ ক্ষতি কৰাৰ অভিযোগ তুলি দলটোৰ সৈতে কোনো বুজাবুজি নোহোৱাৰ কথা কয়। আনহাতে, ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰে দলীয় নেতৃত্ব আৰু ভূগমূল কৰ্মীসকলৰ সহযোগত নিৰ্বাচনত জয়লাভৰ বাবে কাম কৰাৰ সংকল্প প্ৰকাশ কৰে।

ইফালে বিৰোধী দলপতি ৰাজেন আলী চৌধুৰীয়ে এআইইডিএফে হেঁচাৰ বাবেই প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰা বুলি অভিযোগ কৰে।

## সাপ্তাহিক জেন জেন বিচাৰ

Guwahati, 14 August, 2026 Friday :: গুৱাহাটী, শাওণ, শুক্ল পক্ষ, দ্বিতীয়া, শকাব্দ ১৯৪৮



স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ প্ৰাক্কণত 'হৰ ঘৰ তিৰংগা' অভিযানৰ অধীনত গুৱাহাটীত আয়োজিত 'তিৰংগা যাত্ৰা' সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰা লোকসকল।



### অসমত বান

#### পৰিস্থিতিৰ কিছু উন্নতি

গুৱাহাটী: অসমত বান পৰিস্থিতিৰ কিছু উন্নতি ঘটিছে যদিও ৰাজ্যৰ চাৰিখন জিলাত এতিয়াও ৭৭,৫০০ৰো অধিক লোক বানৰ কবলত আছে। অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ তথ্য অনুসৰি, গোলাঘাট সৰ্বাধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত জিলা; জিলাখনত প্ৰায় ৩৫ হাজাৰ লোক বানত প্ৰভাৱিত হৈছে। নগাঁৱত প্ৰায় ২০ হাজাৰ আৰু শিৱসাগৰত প্ৰায় ১৩ হাজাৰ লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে।

অৱশ্যে চলিত বছৰৰ বানত মৃতকৰ সংখ্যা ১০৩জনতে স্থিৰ আছে। ৰাজ্যৰ গোলাঘাট, যোৰহাট, নগাঁও আৰু শিৱসাগৰত মুঠ ৭০টা সাহায্য শিবিৰ আৰু বিতৰণ কেন্দ্ৰ চলি আছে। এই শিবিৰসমূহত ৭,৩৫৮জন লোকক সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছে।

# নাগালেণ্ডৰ খনন কাৰ্যৰ বাবেই উজনি অসমত বানৰ তীব্ৰতা বৃদ্ধি: জাদৱ পায়েঙৰ অভিযোগ

### জন জন বিচাৰ

...যোৰহাট

উজনি অসমত যোৱা মাহত সংঘটিত ভয়াৱহ বানৰ কাৰণক লৈ চলি থকা চৰ্চাৰ মাজতে পদ্মশ্ৰী সন্মানপ্ৰাপ্ত পৰিৱেশ সংৰক্ষক জাদৱ পায়েঙে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। পায়েঙৰ মতে, চুবুৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ডত ব্যাপকভাৱে চলি থকা কয়লা খনন আৰু শিলৰ কুৱেৰীৰ ফলত পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য নষ্ট হৈছে আৰু তাৰ ফলত বিপুল পৰিমাণৰ পানী পোনপটীয়াকৈ উজনি অসমৰ সমতল অঞ্চললৈ নামি আহি বানৰ তীব্ৰতা বৃদ্ধি কৰিছে।

‘ভাৰতৰ বন মানুহ’ হিচাপে পৰিচিত পায়েঙে কয় যে নাগালেণ্ডৰ পাহাৰসমূহত ব্যাপক খনন আৰু শিল কটা কাৰ্যৰ ফলত বহু অঞ্চলৰ পাহাৰ যেন সুৰংগত পৰিণত হৈছে। ফলত বৰষুণৰ পানী স্বাভাৱিক জলপ্ৰবাহৰ পথ অনুসৰণ নকৰি পাহাৰৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ তললৈ বৈ আহিছে। ইয়াৰ ফলত সাধাৰণতে বানৰ প্ৰভাৱ তুলনামূলকভাৱে কম হোৱা অঞ্চলতো পানী সোমাই পৰিছে



বুলি তেওঁ দাবী কৰে।

পায়েঙে বানৰ পূৰ্বে পৰ্যাপ্ত সতৰ্কবাণী জাৰি নকৰাৰ বিষয়টোও উত্থাপন কৰে। তেওঁৰ প্ৰশ্ন-পানী পাহাৰৰ পৰা নামি অহাৰ আগতেই নাগালেণ্ড প্ৰশাসনে কিয় আগতীয়াকৈ সতৰ্কবাণী জাৰি নকৰিলে? তেওঁৰ মতে, সময়মতে সতৰ্কবাণী লাভ নকৰাৰ ফলত বহু লোকক সুৰক্ষিত স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ সুযোগ নাথাকিল

আৰু ক্ষয়-ক্ষতি অধিক বৃদ্ধি পালে।

#### বান-খননীয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা কৰাৰ দাবী

জাদৱ পায়েঙে স্পষ্টভাৱে কয় যে অসমত প্ৰতি বছৰে দেখা দিয়া বান আৰু খননীয়াৰ সমস্যাক কেৱল ৰাজ্য চৰকাৰৰ দায়িত্ব হিচাপে এৰি দিব নালাগে। এই সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে স্বীকৃতি দি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনত এক

সমন্বিত আৰু দীৰ্ঘম্যাদী

সমাধানৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে।

তেওঁ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক বিষয়টো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত গুৰুত্বসহকাৰে উত্থাপন কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। বান আৰু খননীয়াৰ স্থায়ী সমাধানৰ বাবে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজত অধিক সমন্বয়ৰ প্ৰয়োজন বুলি তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰে।

#### কাজিৰঙাৰ পৰিৱেশ সুৰক্ষাক লৈও সতৰ্কবাণী

ইফালে কাজিৰঙাৰ পৰিৱেশ-সংবেদনশীল অঞ্চলৰ পৰিসৰ ১০ কিলোমিটাৰৰ পৰা ১ কিলোমিটাৰলৈ হ্ৰাস কৰাৰ অসম চৰকাৰৰ প্ৰস্তাৱক লৈও পায়েঙে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে। তেওঁৰ মতে, এনে পৰিসৰ হ্ৰাস কৰিলে মানুহ-হাতী সংঘাত বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা আছে।

তেওঁ কয় যে বানৰ সময়ত ১০ কিলোমিটাৰ পৰিসৰৰ ভিতৰতো বন্যপ্ৰাণীৰ নিৰাপদ চলাচল কঠিন হৈ পৰে। এনে পৰিস্থিতিত সংৰক্ষিত অঞ্চলৰ সুৰক্ষা পৰিসৰ ১ কিলোমিটাৰলৈ হ্ৰাস কৰিলে বন্যপ্ৰাণীৰ স্বাভাৱিক চলাচল অধিক বাধাগ্ৰস্ত হ'ব আৰু বহু জীৱ-জন্তুৰ জীৱন বিপদাপন্ন হ'ব পাৰে।

#### বানৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত

##### অব্যাহত অনুসন্ধান

উজনি অসমৰ শেহতীয়া বানক ৰাজ্যখনে বিগত কেইবাদশকৰ ভিতৰত অন্যতম ভয়াৱহ বান হিচাপে অভিহিত কৰিছে। বানৰ প্ৰকৃত কাৰণ সন্দৰ্ভত চৰকাৰী পৰ্যায়ত বিভিন্ন দিশ পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা উপনৈসমূহলৈ বানৰ প্ৰৱণতা সলনি হোৱা আৰু ভাৰত মহাসাগৰৰ দিমেকৰ দৰে জলবায়ুগত পৰিঘটনাই বৰষুণৰ ধৰণত প্ৰভাৱ পেলাৱাৰ সম্ভাৱনাও চৰকাৰে বিবেচনা কৰিছে।

এই পৰিপ্ৰেক্ষিতত জাদৱ পায়েঙৰ নাগালেণ্ডৰ খনন আৰু ভূমি ব্যৱহাৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ অভিযোগে উজনি অসমৰ বানৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত বিতৰ্কক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে।

বান কেৱল প্ৰতি বছৰৰ দুৰ্যোগ নহয়-ই অসমৰ দীৰ্ঘদিনীয়া অস্তিত্বৰ সংকট। সেয়েহে তাৎক্ষণিক সাহায্যৰ লগতে ইয়াৰ মূল কাৰণ চিনাক্ত কৰি আন্তঃৰাজ্যিক সহযোগিতাৰে স্থায়ী সমাধানৰ পথ বিচাৰোৱেই এতিয়া সময়ৰ দাবী।

বন্দে মাতৰম  
স্বাধীনতা দিৱসৰ

## কাৰ্যসূচী বৰ্জনৰ আহ্বান

কোহিমা : নাগালেণ্ডৰ নাগা ছাত্ৰ ফেডাৰেচন (এনএছএফ) আৰু আও ছাত্ৰ সমিলন (একে এম)-এ বিদ্যালয় আৰু শিক্ষানুষ্ঠানসমূহক ১৫ আগষ্টৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ চৰকাৰী কাৰ্যসূচীলৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী নপঠিয়াবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। চৰকাৰী অনুষ্ঠানত সংশোধিত 'বন্দে মাতৰম' বাধ্যতামূলকভাৱে গোৱা বা বজোৱাৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰি সংগঠন দুটাই এই আহ্বান জনাইছে। এনএছএফে স্পষ্ট কৰিছে যে স্বাধীনতা দিৱস পালন, জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীত আৰু অন্যান্য ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীকৰ প্ৰতি সম্মান প্ৰদৰ্শনত তেওঁলোকৰ কোনো আপত্তি নাই। তেওঁলোকৰ আপত্তি কেৱল 'বন্দে মাতৰম'ত বাধ্যতামূলক অংশগ্ৰহণক লৈ।

ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে সংবিধানৰ বিবেক আৰু ধৰ্মীয় স্বাধীনতাৰ অধিকাৰৰ লগতে ৩৭১ অনুচ্ছেদৰ উল্লেখ কৰি কয় যে ধৰ্মীয় বিশ্বাস বা বিবেকৰ সৈতে সংঘাত সৃষ্টি কৰিব পৰা কোনো কাৰ্যসূচীত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বাধ্য কৰা উচিত নহয়। লগতে এনে কাৰ্যসূচীত অংশ নোলোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা, বৈষম্য বা শৈক্ষিক ক্ষতি নকৰিবলৈ দাবী জনোৱা হৈছে।

ৰহাত সুলভ মূল্যত দাইল-চেনী  
বিতৰণ আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ মুখ্যমন্ত্ৰীৰজন জন বিচাৰ  
...ৰহা

ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ অধীনৰ ৰেচন কাৰ্ডধাৰী পৰিয়ালসমূহৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ যোগান বিভাগৰ ৰাজ সাহায্যপাণ্ড সুলভ মূল্যৰ দাইল আৰু চেনী বিতৰণ আঁচনিৰ ৰহাত শুভাৰম্ভ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।

ৰহাৰ কাৰ্য্যকৰণৰ সুৰেণ পাতৰৰ সুলভ মূল্যৰ দোকানত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আঁচনিখনৰ আনুষ্ঠানিক শুভাৰম্ভ কৰে। এই উপলক্ষে তেওঁ কেইবাগৰাকীও ৰেচন কাৰ্ডধাৰীৰ মাজত সুলভ মূল্যত চেনী আৰু মচুৰ দাইল বিতৰণ কৰে।

অনুষ্ঠানৰ পাছত সাংবাদিকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই আঁচনিৰ জৰিয়তে অসমৰ ৭০ লাখৰো অধিক পৰিয়াল উপকৃত হ'ব। বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে চেনী, দাইল আৰু নিমখ-এই তিনিওবিধ আত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী সুলভ মূল্যত যোগান ধৰাৰ

পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে।

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে বাজেট সম্পৰ্কীয় কিছু বিলম্বৰ বাবে চলিত বৰ্ষত নিমখ যোগান ধৰিব পৰা হোৱা নাই। অৱশ্যে অতি শীঘ্ৰেই চেনী আৰু দাইলৰ লগতে নিমখো সুলভ মূল্যত হিতাধিকাৰীসকলক যোগান ধৰা হ'ব

আলোচনাৰ জৰিয়তে  
সমাধানৰ প্ৰচেষ্টা

পৰিস্থিতি শান্ত কৰাৰ বাবে গালো কল্যাণ সমাজ আৰু মিচিং জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ মাজত আলোচনা চলি আছে। একেদৰে দুয়োখন ৰাজ্যৰ যুৱ সংগঠনসমূহও বিষয়টো লৈ আলোচনাত মিলিত হৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰ্যায়তো পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ আৰু স্থায়ী সমাধানৰ বাবে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। লিকাৱালিত বৃহস্পতিবাৰে অসম আৰু অৰুণাচলৰ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, নাগৰিক সমাজৰ প্ৰতিনিধি, ছাত্ৰ আৰু যুৱ সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিসকলক লৈ এখন বৈঠকৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। বৈঠকখনৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল

পৰিস্থিতি পৰ্যালোচনা কৰি শান্তি পুনৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ পথ বিচৰা।

খান্দুৱে কয়, "অসম আৰু অৰুণাচল বহুবছৰ ধৰি শান্তিপূৰ্ণভাৱে একেলগে বাস কৰি আহিছে। আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ব লাগে শান্তিপূৰ্ণ সহাবস্থান বজাই ৰাখি একেলগে আগবাঢ়ি যোৱা।"

## সীমা বিবাদ আলোচনাৰ

## মাধ্যমেৰে সমাধানৰ আশা

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্ট কৰে যে অসম-অৰুণাচল সীমা বিবাদৰ বৃহত্তৰ বিষয়টো দুয়োখন ৰাজ্যৰ দ্বাৰা গঠিত আঞ্চলিক সমিতিৰ জৰিয়তে সমাধানৰ চেষ্টা চলি আছে। অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত এই প্ৰক্ৰিয়া কিছু ধীৰগতি লাভ কৰিছিল যদিও সমিতিসমূহ পুনৰ্গঠন কৰাৰ পাছত পুনৰ আলোচনা আৰম্ভ হৈছে। তেওঁ কয় যে সীমান্ত সম্পৰ্কীয় যিকোনো বাকী থকা বিষয় আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে সমাধান কৰা হ'ব।

## সামাজিক সম্পৰ্ক

## অটুট ৰখাৰ আহ্বান

খান্দুৱে বশেষভাৱে অসম আৰু অৰুণাচলৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগোষ্ঠীসমূহৰ মাজৰ

সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক সম্পৰ্ক অটুট ৰখাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। আদি-গালো আৰু মিচিং জনগোষ্ঠীৰ মাজত দীৰ্ঘদিনীয়া সামাজিক সম্পৰ্ক আছে আৰু বিভিন্ন উৎসৱ-পাৰ্বণ আৰু সামাজিক অনুষ্ঠানত দুয়োটা জনগোষ্ঠীয়ে পৰস্পৰৰ সৈতে মিলিত হৈ আহিছে।

শেহতীয়া ঘটনাই এনে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্কত অনাকাঙ্ক্ষিত দূৰত্বৰ সৃষ্টি কৰা বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ দুয়োপক্ষকে কোনো কাৰণতে পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত নকৰিবলৈ আহ্বান জনায়।

## অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ নীয়ে

## প্ৰত্যাহাৰৰ আশা

বৰ্তমান চলি থকা অৰ্থনৈতিক অৱৰোধৰ সন্দৰ্ভতো মুখ্যমন্ত্ৰী খান্দুৱে পৰিস্থিতি পৰিপক্বতাৰে মোকাবিলা কৰাৰ আশা প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ শীঘ্ৰে অৱৰোধ প্ৰত্যাহাৰ হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰি কয় যে শান্তি আৰু স্বাভাৱিক পৰিস্থিতি বজাই ৰখাৰ বাবে চৰকাৰে প্ৰয়োজনীয় সকলো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব।

## এই সপ্তাহৰ বাৰ্শিক ফল

১৪ আগস্ট, ২০২৬ৰ পৰা ২০ আগস্ট, ২০২৬লৈ

**মেঘ :** আহেটুকু চিন্তা বৃদ্ধি। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত বাধাৰ সম্মুখীন হ'ব পাৰে। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত শুভ।

**বৃষ :** মানসিক অস্থিৰতা থাকিব। কৰ্মক্ষেত্ৰ উন্নতিৰ সম্ভাৱনা আছে। অদৰ্কাৰী প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা ক্ষতি হ'ব পাৰে।

**মিথুন :** আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব। বিদ্যাৰ্থীৰ শুভ। আত্মীয় স্বজনৰ পৰা আনন্দ লাভ।

**কৰ্কট :** আৰ্থিক আগমনত বাধা। চেষ্টাৰ সাফল্য লাভ। মানসিক অস্থিৰতা হ্ৰাস।

**সিংহ :** খৰচ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আছে। আনাৱসাক দুৰ্ভাৱনাৰ পৰা বিৰত থাকক। অদৰ্কাৰী কথাত চেষ্টা পৰা প্ৰদৰ্শনৰ পৰা বিৰত থাকক।

**কন্যা :** সামাজিক ক্ষেত্ৰৰ পৰা মানসিক অস্থিৰতা বৃদ্ধি। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত শুভ। আত্মীয় স্বজনৰ মাজত সমাদৰ বৃদ্ধি।

**তুলা :** কৰ্মক্ষেত্ৰত দৰকাৰী বাক্য বিনিময়ৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব। ব্যয় বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আছে। মানসিক অস্থিৰতা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে।

**বৃশ্চিক :** কৰ্মক্ষেত্ৰত অদৰ্কাৰী আপজব আহিব পাৰে। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত শুভ। ব্যয় বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আছে।

**ধনু :** পিতৃৰ শৰীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সচেতন হ'ব। অত্যধিক আনন্দ ফুটিব পৰা মানসিক পীৰা আহিব পাৰে। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত শুভ।

**মকৰ :** পতি পত্নীৰ মাজত মনোমালিন্য হ'ব পাৰে। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত শুভ। কৰ্মক্ষেত্ৰত সুনাম বৃদ্ধি।

**কুম্ভ :** দৈনন্দিন বাৰ্তা বিনিময়ৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব। প্ৰতিযোগিতা মূলক কাৰ্য্যত সফলতা লাভ। কৰ্মব্যস্ততা বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আছে।

**মীন :** মানসিক চিন্তা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। ঘৰুৱা সন্তি শৃংখলা বজায় ৰখাত অসুবিধা হ'ব পাৰে। কৰ্মক্ষেত্ৰত সুনাম বৃদ্ধি।

-হিতেন শৰ্মা শাস্ত্ৰী

অধ্যাপক, বিশ্ব জ্যোতিষ বিদ্যাপীঠ, অসম শাখা  
যোগাযোগ : ৯৮৫৪০২৬৭৭৯



# মেঘালয়ত ভোটাৰ তালিকা সংশোধনৰ সুযোগ

জন জন বিচাৰ

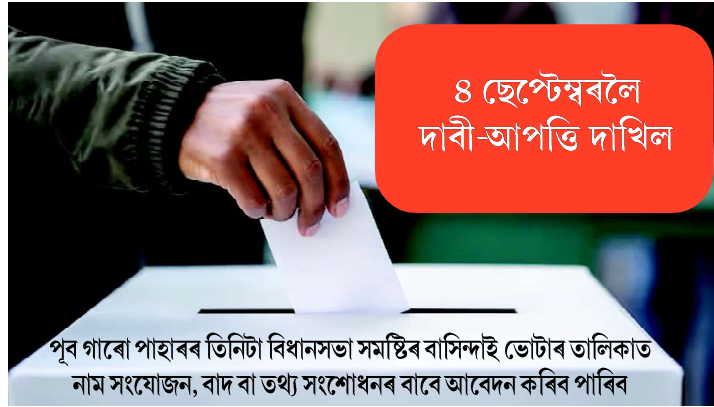
...শিলং

মেঘালয়ৰ পূব গাৰো পাহাৰ জিলাৰ তিনিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰসকলৰ বাবে ভোটাৰ তালিকা সংশোধনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সুযোগ মুকলি হৈছে। জিলাখনৰ ৪১-সংসদ (অনুসূচিত জনজাতি), ৪২-১ (অনুসূচিত জনজাতি) আৰু ৪৩-উইলিয়ামনগৰ (অনুসূচিত জনজাতি) বিধানসভা সমষ্টিৰ খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। তালিকাখনৰ সন্দৰ্ভত দাবী বা আপত্তি দাখিলৰ অন্তিম তাৰিখ ৪ ছেপ্টেম্বৰ, চম্ভাছ।

নিৰ্বাচনী পঞ্জীয়ন বিষয়াসকলে ১৯৬০ চনৰ নিৰ্বাচন পঞ্জীয়ন বিধি অনুসৰি এই খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে। সংশ্লিষ্ট সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী পঞ্জীয়ন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ লগতে পূব গাৰো পাহাৰ জিলাৰ উপায়ুক্তৰ নিৰ্বাচন শাখাৰ কাৰ্যালয়ত কৰ্মদিনত তালিকাসমূহ পৰিদৰ্শনৰ বাবে উপলব্ধ কৰা হৈছে।

এই সংশোধনী প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগ্যতাৰ তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ১ অক্টোবৰ, ২০২৬। অৰ্থাৎ যিসকল নাগৰিকে এই তাৰিখৰ ভিতৰত ১৮ বছৰ বয়স সম্পূৰ্ণ কৰিব, তেওঁলোকেও ভোটাৰ হিচাপে পঞ্জীয়নৰ বাবে আগতীয়াকৈ আবেদন কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছে।

ভোটাৰ তালিকাত নিজৰ নাম সংযোজন কৰিব বিচৰা যোগ্য নাগৰিকে ফৰ্ম-৬ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। কোনো অনুপযুক্ত বা



অযোগ্য ব্যক্তিৰ নাম তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা বুলি আপত্তি থাকিলে ফৰ্ম-৭ আৰু ইতিমধ্যে থকা ভোটাৰ তালিকাৰ নাম, ঠিকনা বা অন্যান্য

তথ্য সংশোধনৰ বাবে ফৰ্ম-৮ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল- ১ অক্টোবৰ, ২০২৬ তাৰিখে ১৮

বছৰ বয়স সম্পূৰ্ণ কৰিবলগীয়া যুৱক-যুৱতীসকলেও বৰ্তমানৰ পৰাই ফৰ্ম-৬ৰ জৰিয়তে আগতীয়াকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। এই

## ইউৰেনিয়াম খননৰ বিৰুদ্ধে মেঘালয় কেবিনেটৰ প্ৰস্তাৱ

শিলং। মেঘালয়ত ইউৰেনিয়াম খননৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য চৰকাৰে আনুষ্ঠানিক স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে। বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত ৰাজ্যখনত ইউৰেনিয়াম খননৰ বিৰোধিতা কৰি বিধানসভাত উত্থাপন কৰিবলগীয়া খচৰা প্ৰস্তাৱত অনুমোদন জনোৱা হয়।

মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড কে. ছাংমাই কেবিনেট বৈঠকৰ পিছত এই সিদ্ধান্তৰ কথা ঘোষণা কৰে। তেওঁ কয় যে 'মেঘালয় ৰাজ্যত ইউৰেনিয়াম খননৰ বিৰুদ্ধে প্ৰস্তাৱ' শীৰ্ষক খচৰাত কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে।

আগন্তুক ২৪ আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া মেঘালয় বিধানসভাৰ শৰৎকালীন অধিবেশনত এই

প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰা হ'ব। ইয়াৰ জৰিয়তে ইউৰেনিয়াম খননৰ সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰৰ আনুষ্ঠানিক মতামত বিধানসভাৰ মজিয়াত স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ পাব।

মেঘালয়ত দীৰ্ঘদিন ধৰি ইউৰেনিয়াম খনন এক বিতৰ্কিত বিষয় হৈ আহিছে। সম্ভাৱ্য পৰিৱেশগত ক্ষতি, জনস্বাস্থ্য আৰু স্থানীয় সমাজ-জীৱনৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱক লৈ বিভিন্ন মহলত উদ্বেগ প্ৰকাশ পাই আহিছে।

আগন্তুক বিধানসভাৰ অধিবেশনৰ পূৰ্বে কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰা এই সিদ্ধান্তই বিষয়টোক পুনৰ চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰলৈ আনিছে। এতিয়া বিধানসভাত প্ৰস্তাৱটো কেনেদৰে আলোচনা আৰু গৃহীত হয়, সেয়া বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে।

আবেদনসমূহ যোগ্যতাৰ তাৰিখৰ সৈতে সম্পৰ্কিত ২০২৬ চনৰ সংশ্লিষ্ট ত্ৰৈমাসিকত পৰীক্ষা কৰি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব।

দাবী আৰু আপত্তি সংশ্লিষ্ট নিৰ্বাচনী পঞ্জীয়ন বিষয়াৰ কাৰ্যালয় অথবা পূব গাৰো পাহাৰ জিলাৰ উপায়ুক্তৰ নিৰ্বাচন শাখাত পোনপটীয়াকৈ দাখিল কৰিব পাৰিব। ডাকযোগেও আবেদন প্ৰেৰণৰ সুবিধা আছে। অৱশ্যে ডাকযোগে প্ৰেৰণ কৰা আবেদন ৪ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত সংশ্লিষ্ট কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱাটো বাধ্যতামূলক।

ভোটাৰ তালিকা এখন কেৱল নিৰ্বাচনী নথি নহয়; ই গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ মূল আধাৰ। সেয়েহে যোগ্য নাগৰিকসকলে খচৰা তালিকাত নিজৰ নাম আৰু তথ্য সঠিকভাৱে আছে নে নাই পৰীক্ষা কৰি চোৱাটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ।

বিশেষকৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোটাৰ হ'বলৈ আগবঢ়া যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবে এই সুযোগ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। সময়সীমাৰ ভিতৰত আবেদন দাখিল কৰি ভোটাৰ তালিকাত নিজৰ নাম নিশ্চিত কৰাটো নাগৰিক দায়িত্বৰ লগতে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ। ৪ ছেপ্টেম্বৰৰ সময়সীমা পাৰ হোৱাৰ পূৰ্বেই সংশ্লিষ্ট নাগৰিকসকলক ভোটাৰ তালিকা পৰীক্ষা কৰি প্ৰয়োজনীয় দাবী, আপত্তি বা সংশোধনৰ আবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্বাচনী কৰ্তৃপক্ষই আহ্বান জনাইছে।

## কমনৱেলথত ৰূপৰ পদক জয়ী লাভলীনাক ৩০ লাখ টকাৰ সন্মান

জন জন বিচাৰ

...গুৱাহাটী

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত পুনৰ অসমৰ নাম উজলাই তুলিলে অসম কন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁইয়ে। ২০২৬ চনৰ গ্লাছগো কমনৱেলথ গেমছত মহিলাৰ ৭৫ কিলোগ্ৰাম শাখাত ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰা লাভলীনাক দিছপুৰৰ লোক সেৱা ভৱনত ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে সন্মৰ্ষনা জনোৱা হয়।

অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লাভলীনাৰ হাতত ৩০ লাখ টকাৰ চেক অৰ্পণ কৰে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত লাভলীনাৰ ধাৰাবাহিক সফলতা, দৃঢ়তা আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ প্ৰশংসা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে তেওঁৰ এই কৃতিত্ব কেৱল অসমৰ বাবেই নহয়, সমগ্ৰ দেশৰ বাবেও গৌৰৱৰ বিষয়।



মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে লাভলীনাৰ সফলতাই অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মক প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি অধিক আগ্ৰহী কৰি তুলিব। তেওঁৰ যাত্ৰাই কঠোৰ পৰিশ্ৰম, অধ্যৱসায় আৰু আত্মবিশ্বাসৰ জৰিয়তে লক্ষ্যত

উপনীত হ'ব পাৰি বুলি নতুন প্ৰজন্মক শিক্ষা দিয়ে।

নৰপ্ৰজন্মৰ বাবে আদৰ্শ লাভলীনাক উচ্চাৰণক্ষী খেলুৱৈসকলৰ বাবে এক আদৰ্শ হিচাপে অভিহিত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে

আশা প্ৰকাশ কৰে যে আগন্তুক দিনতো তেওঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া মঞ্চত দেশৰ হৈ অধিক সন্মান কঢ়িয়াই আনিব।

গ্লাছগো কমনৱেলথ গেমছ আছিল লাভলীনাৰ প্ৰথম

কমনৱেলথ পদক। মহিলাৰ ৭৫ কিলোগ্ৰাম শাখাৰ ফাইনেলত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ এমা-ছু গ্ৰীনট্ৰিৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ অন্তত পৰাস্ত হৈ তেওঁ ৰূপৰ পদক লাভ কৰে।

মুখ্যমন্ত্ৰীক ভাৰতীয় দলৰ জাৰ্জি উপহাৰ

সন্মৰ্ষনা অনুষ্ঠানত লাভলীনাৰ কমনৱেলথ গেমছৰ স্মৃতি হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ভাৰতীয় দলৰ দুখন জাৰ্জি উপহাৰ দিয়ে। অনুষ্ঠানত ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ মন্ত্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব কে কে দিবেদী আৰু ক্ৰীড়া বিভাগৰ বিশেষ সচিব কে জে হিলালীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। লাভলীনাৰ এই সাফল্যই আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে-সুযোগ, সংকল্প আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম একেলগে থাকিলে অসমৰ মাটিৰ পৰাও বিশ্ব ক্ৰীড়াৰ মঞ্চত বিজয়ৰ পতাকা উৰুৱাব পাৰি।

## সম্পাদকীয় সীমান্তৰ সুৰক্ষা লৈ ৰাজনীতি নহয়, স্বচ্ছতাই হওক ৰাষ্ট্ৰীয় স্বার্থৰ প্ৰথম চৰ্ত

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এল এ চিৰ কাষত ভাৰতীয় সেনাৰ পৰম্পৰাগত টহলদাৰীত চীনে বাধা দিয়া বুলি ৰাখল গান্ধীয়ে উত্থাপন কৰা অভিযোগে দেশৰ সীমান্ত সুৰক্ষাৰ লৈ নতুন উদ্বোধন সৃষ্টি কৰিছে। অৱশ্যে এই অভিযোগৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কোনো আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকৰণ প্ৰকাশ পোৱা নাই। সেয়ে অভিযোগক সত্য বুলি ধৰি লোৱাৰ সলনি চৰকাৰৰ পৰা স্পষ্ট তথ্য বিচৰাটোৱেই গণতান্ত্ৰিকভাৱে অধিক দায়িত্বশীল

পথ।

ভাৰত-চীন সীমান্তৰ বিষয়টো কোনো দলীয় ৰাজনীতিৰ বিষয় হ'ব নোৱাৰে। গালবানৰ পিছত সীমান্তত শান্তি আৰু স্থিৰতা বজাই ৰখা, সেনাৰ স্বার্থ সুৰক্ষিত কৰা আৰু কূটনৈতিক আলোচনাৰ জৰিয়তে সমস্যাৰ সমাধান বিচৰা-এই তিনিওটা দিশ সমান গুৰুত্বপূৰ্ণ।

যদি টাকচিং বা আপাৰ সুবনশিৰিৰ দৰে অঞ্চলত ভাৰতীয় সেনাৰ পৰম্পৰাগত টহলদাৰীত সঁচাকৈয়ে বাধা সৃষ্টি হৈছে, তেন্তে বিষয়টো অত্যন্ত গুৰুতৰ। চৰকাৰে সংসদ আৰু দেশবাসীক যথাসম্ভৱ তথ্য জনোৱা উচিত। একে সময়তে, সংবেদনশীল সামৰিক তথ্য ৰাজহুৱা কৰি সীমান্তত থকা জোৱানসকলৰ সুৰক্ষা বা কূটনৈতিক স্থিতি দুৰ্বল কৰাটোও সমীচীন নহয়।

বিৰোধী দলৰ দায়িত্ব হৈছে চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰা; চৰকাৰৰ দায়িত্ব হৈছে সেই প্ৰশ্নৰ যুক্তিসংগত উত্তৰ দিয়া। কিন্তু সীমান্তৰ দৰে স্পৰ্শকাতৰ বিষয়ত অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ আৰু সংবাদমাধ্যমক লৈ সন্দেহৰ পৰিৱেশে দেশৰ স্বার্থকহে ক্ষতি কৰিব পাৰে।

চীনৰ সৈতে ভাৰতৰ সীমান্ত বিবাদ দীৰ্ঘদিনীয়া আৰু জটিল। সেয়েহে ইয়াত আবেগ নহয়, তথ্য, একা, কূটনীতি আৰু দৃঢ় ৰাষ্ট্ৰীয় স্থিতিৰ প্ৰয়োজন। অৰুণাচলৰ সীমান্তত ভাৰতৰ এক ইঞ্চি ভূমিৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো আপোচ চলিব নোৱাৰে। কিন্তু সেই সুৰক্ষাৰ স্বার্থতেই বিষয়টোক ৰাজনৈতিক উত্তেজনাৰ পৰা আঁতৰাই জাতীয় একাৰ ভিত্তিত স্বচ্ছ আৰু দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লাগিব।

# ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতৰ নীৰৱতাত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল

জন জন বিচার

...সুজল প্ৰধান

প্ৰতিজন ভাৰতীয় শিশুৱে বিদ্যালয়ত থিয় হৈ 'জন গণ মন' গাবলৈ শিকে। পঞ্জাব, সিন্ধু, গুজৰাট, মাৰাঠা, দ্ৰাবিড়, উৎকল, বঙ্গ-এই নামবোৰে ভাৰতীয় জাতীয় চেতনাৰ এক প্ৰতীকী ভূগোল গঢ়ি তোলে। হিমালয়, বিন্ধ্য, গংগা আৰু যমুনাৰ উল্লেখ দেশখনৰ ভৌগোলিক বিস্তাৰকো আমাৰ মনত প্ৰতিষ্ঠা কৰে।

কিন্তু এই পৰিচিত শব্দমালাৰ মাজত এটা বৃহৎ অঞ্চলৰ নাম নাই-উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল।

এই অনুপস্থিতি কেৱল এটা শব্দ নথকাৰ বিষয় নে ইয়াৰ আঁতৰ আছে অধিক গভীৰ এক 'মানসিক অদৃশ্যতা'? এই প্ৰশ্নটোৱেই নতুনকৈ চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে।

গীতটো কেৱল গীত নহয়, এক সাহুহিক অনুভৱৰ অনুষ্ঠান

জাতীয় সংগীত এখন তথ্যপুথি নহয়। ই ভাৰতৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ নাম উল্লেখ কৰাৰ বাবে ৰচনা কৰা হোৱা নাই। ইয়াৰ মূল শক্তি হৈছে-ই মানুহক একেলগে থিয় কৰায়, একেলগে গাবলৈ দিয়ে আৰু একে সময়তে এক সাহুহিক জাতীয় অনুভূতিৰ সৈতে সংযুক্ত কৰে।

যোগাযোগ তন্ত্ৰৰ ভাষাত ইয়াক 'ফেক্টিক কমিউনিকেশ্যন' বা সাহুহিক সংযোগ সৃষ্টিকাৰী আনুষ্ঠানিক ভাষা বুলি ব্যাখ্যা কৰিব পাৰি। অৰ্থাৎ জাতীয় সংগীতৰ প্ৰতিটো শব্দতকৈও গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈছে সেই মূহুৰ্ত্তত সৃষ্টি হোৱা 'আমি এক'ৰ অনুভৱ।

সেইবাবেই ইয়াত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ অনুপস্থিতিৰ প্ৰশ্নটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰে। এগৰাকী উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ শিশুৱে প্ৰতিদিনে জাতীয় সংগীত গায়, কিন্তু নিজৰ ঘৰ, নিজৰ অঞ্চলৰ কোনো উল্লেখ নাপায়। তেওঁ জাতীয় অনুষ্ঠানটোৰ অংশ, কিন্তু অনুষ্ঠানটোৰ শব্দত নিজৰ পৰিচয় বিচাৰি নাপায়-এই বৈপৰীত্যই এক গভীৰ মানসিক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে।

১৯১১ৰ ইতিহাস আৰু এটা অস্বস্তিকৰ প্ৰশ্ন

ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে ১৯১১ চনত 'ভাৰত ভাগ্য বিধাতা' ৰচনা কৰিছিল। ইয়াৰ প্ৰথম স্তৰকেই পিছলৈ ভাৰতৰ জাতীয় সংগীত হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হয়। সেই সময়ৰ ঔপনিৱেশিক প্ৰশাসনিক ভূগোলৰ সৈতে

## দেশৰ মানচিত্ৰত আছোঁ, মনৰ মানচিত্ৰত কিমান?



গীতটোৰ উল্লেখসমূহৰ এক সম্পৰ্ক আছিল। কিন্তু ইয়াতেই এটা প্ৰশ্ন উত্থাপিত হয়- ১৯১১ চনত অসমো ব্ৰিটিছ শাসিত অঞ্চল আছিল। তথাপিও অসমৰ নাম গীতটোত নাছিল। আনহাতে, 'সিন্ধু'ৰ উল্লেখ আজিও জাতীয় সংগীতত আছে, যদিও দেশ বিভাজনৰ পিছত সিন্ধু পাকিস্তানৰ অংশ হৈ পৰে।

ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে ঠাকুৰে ইচ্ছাকৃতভাৱে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলবাদ দিছিল বুলি সিদ্ধান্ত দিব পাৰি। বৰং মূল প্ৰশ্নটো হৈছে- স্বাধীনতাৰ পিছত এই ঐতিহাসিক অনুপস্থিতিৰ বিষয়ে আমি কিমান গভীৰভাৱে আত্মসমীক্ষা কৰিছোঁ?

"হিমালয়ত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল আছে"-এই যুক্তি কিমান যথার্থ?

কেতিয়াবা কোৱা হয় যে জাতীয় সংগীতত 'হিমালয়'ৰ উল্লেখ আছে, সেয়েহে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল পৰোক্ষভাৱে তাত অন্তৰ্ভুক্ত।

কিন্তু পাহাৰৰ নাম আৰু এটা অঞ্চলৰ মানুহৰ পৰিচয় একে কথা নহয়। গীতটোত পঞ্জাব, গুজৰাট বা মাৰাঠাৰ দৰে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ভূগোলৰ উল্লেখ আছে। 'হিমালয়' মূলতঃ এটা ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যৰ উল্লেখ।

সেয়ে প্ৰশ্নটো কেৱল 'উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল'ৰ নাম আছে নে নাই নহয়; প্ৰশ্নটো হৈছে-উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহে জাতীয় কল্পনাত নিজৰ স্বকীয় স্থানটো কিমান স্পষ্টভাৱে অনুভৱ কৰে?

আদালতে নহয়, সমাজেই সলনি কৰিব লাগিব ২০০৫ চনত জাতীয় সংগীতৰ 'সিন্ধু' শব্দ সলনি কৰাৰ দাবীৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এখন আবেদন দাখিল কৰা হৈছিল। আদালতে জাতীয় সংগীতক দেশপ্ৰেম আৰু জাতীয় অনুভূতি প্ৰকাশ কৰা এক গীত হিচাপে বিবেচনা কৰি বিষয়টোত হস্তক্ষেপ কৰা নাছিল।

২০১৮ চনত ৰাজ্যসভাত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল শব্দটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ দাবীৰে ব্যক্তিগত সদস্যৰ প্ৰস্তাৱ উত্থাপন হৈছিল। কিন্তু বিষয়টো আগবঢ়ি নগ'ল।

ইয়াৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট-এই সমস্যাৰ সমাধান কেৱল আদালতৰ জৰিয়তে সম্ভৱ নহয়। ইয়াৰ প্ৰকৃত ক্ষেত্ৰ হৈছে বিদ্যালয়, পাত্ৰপ্ৰসাদ, সংবাদমাধ্যম, জনপ্ৰিয় সংস্কৃতি আৰু আমাৰ দৈনন্দিন সামাজিক আচৰণ।

এক ভাৰত'ৰ শ্লোগান আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল দেশত 'এক দেশ, এক...' ধাৰণাৰ জৰিয়তে একতা আৰু এককণ্ঠতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক আকৌ ভাৰতৰ 'Act East' নীতিৰ কৌশলগত দুৱাৰ হিচাপেও উপস্থাপন কৰা হয়।

কিন্তু এটা অঞ্চলক দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ সৈতে সংযোগ কৰা কৌশলগত কৰিডৰ হিচাপে দেখা আৰু সেই অঞ্চলৰ মানুহক ভাৰতীয় জাতীয় জীৱনৰ স্বাভাৱিক অংশ হিচাপে দেখা-দুটা সম্পূৰ্ণ পৃথক বিষয়।

উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল কেৱল ভাৰতৰ পূৰ্ব সীমান্তৰ কৌশলগত অঞ্চল নহয়। ই কোটি কোটি নাগৰিকৰ বাসভূমি, বহু ভাষা, জাতি, পৰম্পৰা, ইতিহাস আৰু সংস্কৃতিৰ এক সমৃদ্ধ ভূখণ্ড।

সংবাদমাধ্যমতো একেই নীৰৱতা

ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদমাধ্যমৰ ক্ষেত্ৰতো উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ উপস্থিতি বহু সময়ত সংকট, বানপানী, সংঘাত বা প্ৰাকৃতিক দুৰ্ঘটনাৰ দৰে বিশেষ ঘটনাৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকে। অঞ্চলটোৰ দৈনন্দিন জীৱন, শিক্ষা, উদ্যোগ, সাহিত্য, ক্ৰীড়া, সংস্কৃতি আৰু সফলতাৰ কাহিনী দেশৰ মূলসূঁতত তুলনামূলকভাৱে কম স্থান পায়।

ডিজিটেল মাধ্যমৰ উত্থানে অৱশ্যে এই ছবিখনত কিছু পৰিৱৰ্তন আনিছে। উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বহু যুৱ সৃষ্টিকৰ্তাই নিজস্ব মঞ্চ সৃষ্টি কৰি দেশৰ লগতে বিশ্বৰ দৰ্শকৰ ওচৰলৈ গৈছে। কিন্তু ব্যক্তিগত সৃষ্টিকৰ্তাৰ সফলতাই

প্ৰতিষ্ঠানগত বৈষম্য সম্পূৰ্ণৰূপে দূৰ কৰিব নোৱাৰে।

মানসিক মানচিত্ৰত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল ক'ত?

ভাৰতৰ সংবিধানিক মানচিত্ৰত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ স্থানক লৈ কোনো প্ৰশ্ন নাই। অসম, মেঘালয়, মণিপুৰ, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড, ত্ৰিপুৰা, অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু ছিকিম-এই আঠখন ৰাজ্য ভাৰতীয় সংঘৰ অবিচ্ছেদ্য অংশ।

কিন্তু দেশ এখন কেৱল সংবিধান, সীমাৰেখা আৰু প্ৰশাসনিক মানচিত্ৰৰে গঠিত নহয়। দেশ এখন মানুহে নিজৰ মনত সৃষ্টি কৰা এক সাহুহিক কল্পনাও।

সেই কল্পনাৰ ভিতৰত যদি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল বাবে বাবে প্ৰান্তত থাকে, তেন্তে সমস্যাটো কেৱল প্ৰতিনিধিত্ব নহয়-ই জাতীয় আত্মপৰিচয়ৰো সমস্যা।

অসমীয়া ভাষাক বাংলা ভাষাৰ সৈতে একে বুলি ধৰি লোৱা, উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহৰ ভাৰতীয় পৰিচয়ক লৈ অদ্ভুত প্ৰশ্ন কৰা, অথবা তেওঁলোকক কেৱল 'বাহিৰৰ মানুহ' হিচাপে চোৱা-এইবোৰ সেই মানসিক দৃষ্টিৰ প্ৰকাশ।

এই সমস্যাৰ সৈতে জাতিগত বৈষম্য আৰু বৰ্ণবাদী আচৰণৰ ঘটনাও জড়িত হৈ আহিছে। দিল্লীত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নীড়ো তানিয়াৰাম মৃত্যুৰ ঘটনাই এই সমস্যাৰ ভয়ংকৰ ৰূপ দেশৰ সন্মুখত উন্মোচিত কৰিছিল। মহামাৰীৰ সময়তো পূৰ্ব এছিয়া চেহেৰাৰ ভাৰতীয়সকলে 'বৈষম্যৰ সন্মুখীন হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছিল।

অন্তৰ্ভুক্তি মানে কি?

এই আলোচনাৰ উদ্দেশ্য জাতীয় সংগীত সলনি কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰাই নহয়। বৰীন্দ্রনাথ ঠাকুৰে ১৯১১ চনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত গীতটো ৰচনা কৰিছিল। মূল প্ৰশ্নটো হৈছে- স্বাধীনতাৰ ৭৯ বছৰৰো অধিক সময় পিছতো আমি জাতীয় পৰিচয়ৰ প্ৰতীকসমূহৰ ভিতৰত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ উপস্থিতি আৰু স্বীকৃতিৰ বিষয়ে কিয় যথেষ্ট আত্মসমীক্ষা কৰা নাই?

অন্তৰ্ভুক্তি মানে দয়া নহয়। উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক 'বিশেষ' বা 'অন্য' হিচাপে চোৱাৰ পৰিৱৰ্তে পঞ্জাবী, সংস্কৃতি, বাংলা সাহিত্য, তামিল সংগীত বা মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিৰ দৰে স্বাভাৱিকভাৱে ভাৰতীয় জীৱনৰ অংশ হিচাপে চোৱাটোৱেই প্ৰকৃত অন্তৰ্ভুক্তি।



# সংসদীয় সমিতিৰ প্ৰতিবেদনে উন্মোচন কৰিলে বেচৰকাৰী চিকিৎসালয়-বিদ্যালয়ৰ মনমৰ্জি

## জন জন বিচাৰ

...নতুন দিল্লী

দেশত বেচৰকাৰী চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ সংখ্যা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে সাধাৰণ আৰু মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ ওপৰত ইয়াৰ আৰ্থিক বোজাও ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে। চিকিৎসাৰ দৰে জীৱন-মৰণৰ বিষয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সন্তানৰ শিক্ষালৈকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অত্যধিক মাচুল আদায়ৰ অভিযোগে দীৰ্ঘদিন ধৰি জনসাধাৰণক চিন্তিত কৰি আহিছে। এনে সময়তে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ সৈতে জড়িত সংসদীয় স্থায়ী সমিতিৰ এক প্ৰতিবেদনে বেচৰকাৰী চিকিৎসালয়সমূহৰ মাচুল আৰু বিল ব্যৱস্থাৰ ওপৰত গুৰুতৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে।

সমিতিৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাৰ গড় ব্যয় প্ৰায় ৬.৬৩১ টকা, আনহাতে বেচৰকাৰী চিকিৎসালয়ত একেধৰণৰ চিকিৎসাৰ ব্যয় গড়ে ৫০.৫০৮ টকালৈ বৃদ্ধি পায়। অৰ্থাৎ বেচৰকাৰী চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাৰ খৰচ চৰকাৰী চিকিৎসালয়ৰ তুলনাত সাতগুণতকৈও অধিক। ইয়াৰ উপৰি ৰোগীক চিকিৎসা আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে সম্পূৰ্ণ ব্যয়ৰ স্পষ্ট হিচাপ নিদিয়া, বিলত দৃষ্টিভাৱে অসুবিধা আৰু বিভিন্ন সেৱাৰ নামত অতিৰিক্ত

মাচুল আদায়ৰ অভিযোগো সমিতিয়ে গুৰুত্বসহকাৰে উত্থাপন কৰিছে।

আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈছে চিকিৎসালয়ৰ কোঠাৰ ভাড়া। বহু বেচৰকাৰী চিকিৎসালয়ত ৰোগীৰ পৰা আদায় কৰা দৈনিক কোঠাৰ ভাড়া একে অঞ্চলৰ তিনিটা হোটেলৰ ভাড়াতকৈও অধিক বুলি প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে। উদাহৰণস্বৰূপে, মুম্বাইৰ নানাবতী চিকিৎসালয়ত কোঠাৰ বাবে দৈনিক প্ৰায় ৬,০০০-১২,০০০ টকা পৰ্যন্ত আদায় কৰা হয়, য'ত ওচৰৰ তিনিটা হোটেলত

তুলনামূলকভাৱে কম মূল্যতে কোঠা পোৱা যায়। দিল্লীৰ সাকেত অঞ্চলতো বেচৰকাৰী চিকিৎসালয়ত কোঠাৰ ভাড়া ওচৰৰ হোটেলৰ তুলনাত যথেষ্ট অধিক বুলি প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে।

এই পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সংসদীয় সমিতিয়ে বেচৰকাৰী চিকিৎসালয়ৰ কোঠাৰ ভাড়া তিনিটা হোটেলৰ ভাড়াতকৈ অধিক নোহোৱাৰ পৰামৰ্শ দিছে। গুৰুতৰ ৰোগ বা অস্ত্ৰোপচাৰৰ ক্ষেত্ৰত চিকিৎসা আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বেই ৰোগী আৰু পৰিয়ালক মুঠ ব্যয়ৰ স্পষ্ট অনুমান দিবলৈও সমিতিয়ে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। লগতে গুৰুত্বপূৰ্ণ অস্ত্ৰোপচাৰ আৰু চিকিৎসাৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট মাচুল নিৰ্ধাৰণ কৰি তাৰ ভিতৰত সকলো ব্যয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ ব্যৱস্থাৰ কথাও

কোৱা হৈছে।

## চৰকাৰী চিকিৎসা ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰাৰ দাবী

সংসদীয় সমিতিয়ে চৰকাৰী চিকিৎসালয়সমূহত অধিক সংখ্যক শয্যা আৰু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োগৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। কাৰণ চৰকাৰী চিকিৎসা

পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে।

## শিক্ষা ক্ষেত্ৰতো একেই ছবি

বেচৰকাৰী চিকিৎসালয়ৰ সৈতে বেচৰকাৰী বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়সমূহৰ ক্ষেত্ৰতো একেধৰণৰ অভিযোগ দীৰ্ঘদিন ধৰি উত্থাপিত হৈ আহিছে। বিদ্যালয়ৰ নামত মাচুল, নামভৰ্তিৰ মাচুল,

সংগ্ৰহ কৰে। কিন্তু সেই সুবিধা প্ৰকৃততে শিক্ষার্থীৰ শিক্ষাগত উন্নয়নত কিমান ব্যৱহৃত হৈছে, তাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে।

## নিয়ন্ত্ৰণৰ স্থায়ী ব্যৱস্থা কেতিয়া?

সংসদীয় সমিতিয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ আগবঢ়ালেও মূল প্ৰশ্নটো এতিয়াও একেই-বেচৰকাৰী চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ মনমৰ্জি আৰু অত্যধিক মাচুল আদায়ৰ ওপৰত কাৰ্যকৰী নিয়ন্ত্ৰণ কেতিয়া আহিব?

স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষা কোনো বিলাসী সামগ্ৰী নহয়; ই নাগৰিকৰ মৌলিক প্ৰয়োজন। লাভৰ উদ্দেশ্যত চলা প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ বাবে ন্যায্য নিয়ন্ত্ৰণ আৰু স্বচ্ছতা নিশ্চিত কৰাটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব। চিকিৎসাৰ সময়ত ৰোগীক অসহায় অৱস্থাৰ সুযোগ লৈ অত্যধিক ধন আদায় বা শিক্ষাৰ নামত অভিভাৱকৰ ওপৰত অৰৈক্যিক আৰ্থিক বোজা জপি দিয়াটো কোনো সুস্থ সমাজৰ লক্ষণ হ'ব নোৱাৰে।

এতিয়া প্ৰয়োজন কেৱল প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ বা পৰামৰ্শ দিয়াত সীমাবদ্ধ নথকা কঠোৰ, স্বচ্ছ আৰু স্থায়ী নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৱস্থা। চৰকাৰে চিকিৎসা আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণ নাগৰিকৰ স্বাৰ্থক সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দি এনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, যাতে চিকিৎসা আৰু শিক্ষা দুয়োটাই ধনীৰ বাবে কেৱল সুবিধা আৰু দুখীয়াৰ বাবে দুৰ্লভ অধিকাৰ হৈ নপৰে।

চিকিৎসাৰ নামত অত্যধিক মাচুল, কোঠাৰ ভাড়া  
হোটেলতকৈও অধিক; শিক্ষা ব্যৱস্থাতো ফী,  
কিতাপ-কাপোৰৰ নামত অবাধ ধন সংগ্ৰহ-  
কেতিয়া বন্ধ হ'ব এই লুপ্তন?

ব্যৱস্থা শক্তিশালী নহ'লে সাধাৰণ মানুহে বাধ্য হৈ বেচৰকাৰী চিকিৎসালয়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লাগিব আৰু তেনে পৰিস্থিতিত অত্যধিক চিকিৎসা ব্যয়ৰ পৰা ৰক্ষা পোৱাটো কঠিন হৈ পৰিব।

কিন্তু ইয়াত আন এটা আশংকাও আছে। দেশৰ সকলো অঞ্চলৰ চিকিৎসা ব্যয় একে নহয়। দিল্লী, মুম্বাইৰ দৰে মহানগৰৰ চিকিৎসা ব্যয় আৰু অসমৰ গ্ৰামাঞ্চল বা দেশৰ দূৰৱৰ্তী অঞ্চলৰ চিকিৎসা ব্যয়ৰ মাজত স্বাভাৱিকতেই পাৰ্থক্য আছে। সেয়েহে চৰকাৰে যদি মহানগৰৰ ব্যয়ৰ ভিত্তিত সমগ্ৰ দেশৰ বাবে একে হাৰত চিকিৎসা মাচুল নিৰ্ধাৰণ কৰে, তেন্তে ইয়াৰ ফলত সৰু চহৰ আৰু দূৰৱৰ্তী অঞ্চলৰ ৰোগীসকলৰ ওপৰত নতুনকৈ আৰ্থিক বোজা

কিতাপ, পোছাক, পৰিবহণ, বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আৰু এতিয়া 'স্মাৰ্ট ক্লাছ'ৰ নামতো অভিভাৱকৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰা হয়।

বিশেষকৈ বেচৰকাৰী চিকিৎসা শিক্ষাৰ ব্যয় মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ বাবে প্ৰায় অসাধ্য হৈ পৰিছে। বহু বেচৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত এমবিবিএছ শিক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ এক কোটি টকাৰো অধিক ব্যয় হোৱাৰ উদাহৰণ আছে। ফলত মেধাৱী কিন্তু আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল শিক্ষার্থীৰ বাবে চিকিৎসা শিক্ষা লাভ কৰাটো ক্ৰমাৎ কঠিন হৈ পৰিছে।

বিদ্যালয়সমূহতো 'স্মাৰ্ট ক্লাছ'ৰ নামত মাহিলি মাচুল আদায়ৰ অভিযোগ আছে। একাংশ বিদ্যালয়ে 'স্মাৰ্ট ব'ৰ্ড' বা ডিজিটেল শিক্ষাৰ নামত মাহে কেইশ টকাৰ পৰা অধিক মাচুল

# অন্ধবিশ্বাসৰ নামত নাৰী হত্যা: সংবিধানৰ পোহৰত সমাজে কেতিয়া সাৰ পাব?

## জন জন বিচাৰ

...নতুন দিল্লী

ভাৰতীয় সমাজে বিজ্ঞান, প্ৰযুক্তি আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অতীতপূৰ্ব অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। চন্দ্ৰ অভিযানৰ পৰা কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তালৈকে আমি একবিংশ শতিকাৰ দুৱাৰত থিয় হৈছোঁ। কিন্তু এই আধুনিকতাৰ মাজতো যদি কোনো নাৰীক 'ডাইনী' বুলি অপবাদ দি অত্যাচাৰ কৰা হয়, আনকি হত্যা কৰা হয়, তেন্তে প্ৰশ্ন উঠিবই-আমাৰ সামাজিক চেতনাই আচলতে কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে?

উৰিষ্যাৰ ১৯৯৮ চনৰ এটা নাৰী হত্যাৰ গোচৰত শেহতীয়াকৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিয়া মন্তব্যই এই প্ৰশ্নটো পুনৰ দেশৰ সন্মুখলৈ আনিছে। এগৰাকী অসহায় মহিলাক 'ডাইনী' বুলি অপবাদ দি ঘৰৰ পৰা টানি উলিয়াই নৃশংসভাৱে প্ৰহাৰ কৰা হৈছিল আৰু শেষত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অভিযুক্তক দোষী সাব্যস্তকৰণ আৰু আজীবন

কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি বাহাল ৰাখি স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে এনে অন্ধবিশ্বাস আৰু কুসংস্কাৰৰ বিৰুদ্ধে আইনৰ শাসন আৰু সাংবিধানিক নৈতিকতাই জয়ী হ'ব লাগিব।

আদালতে বিশেষভাৱে পৌৰৰাই দিছে যে ভাৰতীয় সংবিধানৰ সমতা, ভাৰতবোধ আৰু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীৰ ওপৰত আধাৰিত এখন সমাজৰ কল্পনা কৰিছে। সেয়ে নাৰীক 'ডাইনী' বুলি অপমান কৰা বা সেই অপবাদৰ ভিত্তিত শাৰীৰিক-মানসিক অত্যাচাৰ চলোৱা কোনো সভ্য সমাজে মানি ল'ব নোৱাৰে।

## 'ডাইনী' অপবাদৰ আঁৰত কোনবোৰ কাৰণ?

ডাইনী বুলি অপবাদ দিয়াৰ ঘটনাৰ আঁৰত কেৱল অন্ধবিশ্বাসেই নাথাকে। বহু সময়ত ইয়াৰ সৈতে সম্পত্তিৰ বিবাদ, পাৰিবাৰিক সংঘাত, ব্যক্তিগত শত্ৰুতা, সামাজিক অধিপত্য

আৰু নাৰীৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ স্থাপনৰ মানসিকতা জড়িত হৈ থাকে।

অসুস্থতা, মৃত্যুৰ ঘটনা, সন্তানৰ সমস্যা বা কোনো অস্বাভাৱিক পৰিস্থিতিৰ বৈজ্ঞানিক কাৰণ বিচৰাৰ সলনি কোনো এগৰাকী মহিলাক দায়ী কৰি পেলোৱাটো সহজ বুলি ধৰা হয়। বিশেষকৈ সমাজৰ দুৰ্বল, একাকী, বিধবা বা সামাজিকভাৱে পিছপৰা মহিলাসকল এনে অপবাদৰ সহজ লক্ষ্য হৈ পৰে।

এটা অপবাদ কেতিয়াবা কেৱল এটা শব্দ হৈ নাথাকে। ই এগৰাকী মহিলাৰ সামাজিক সমান কাৰ্টি ল'ব পাৰে, তেওঁক পৰিয়াল আৰু সমাজৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰিব পাৰে আৰু শেষত তেওঁৰ জীৱনৰ প্ৰতিও ভাবুকি সৃষ্টি কৰিব পাৰে। এগৰাকী শিশুৰ চকুত মাকৰ হত্যাৰ দৃশ্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই গোচৰটো শুনি

কেৱল অপৰাধৰ ভয়কৰতাই নহয়, ঘটনাটোৰ মানৱীয় দিশটোও উত্থাপন কৰিছে। আদালতে সোঁৱৰাই দিছে-বিগৰাকী কন্যাই নিজৰ মাকক অতি নিষ্ঠুৰভাৱে হত্যা কৰা দেখিছিল, সেই শিশুমনৰ ওপৰত এই ঘটনাৰ কি গভীৰ প্ৰভাৱ পৰিছিল, সেয়া কল্পনা কৰাটোও যন্ত্ৰণাদায়ক।

এই কথাটোৱেই দেখুৱায় যে কুসংস্কাৰজনিত হিংসাৰ ক্ষতি কেৱল এগৰাকী ভুক্তভোগীৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নাথাকে। এটা অপৰাধে এটা পৰিয়াল, এটা শিশুৰ মানসিক জগত আৰু সমগ্ৰ সমাজৰ নৈতিক বিবেকক আঘাত কৰে।

## আইন আছে, কিন্তু সামাজিক চেতনাই ক'ত?

অন্ধবিশ্বাসৰ বিৰুদ্ধে আইন প্ৰয়োজনীয়। অপৰাধীৰ কঠোৰ শাস্তিও প্ৰয়োজনীয়। কিন্তু কেৱল শাস্তিৰ ভয় দেখুৱাই এই সামাজিক ব্যাধি সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মূল কৰিব নোৱাৰিব।

বিদ্যালয়ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, সমাজত যুক্তিবাদী চিন্তা আৰু গ্ৰামাঞ্চলত স্বাস্থ্যপ্ৰজ্ঞা, শিক্ষা আৰু আইনী সজাগতাৰ প্ৰসাৰ ঘটাব লাগিব।



# চেতনা দাসলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান: ৰাষ্ট্ৰপতি মূৰ্মুৰ হাতত সংগীত নাটক অকাডেমি বঁটা

জন জন বিচাৰ  
...গুৱাহাটী

অসমীয়া অভিনয় জগতৰ এগৰাকী প্ৰবীণ আৰু জনপ্ৰিয় শিল্পী চেতনা দাসে লাভ কৰিলে দেশৰ অন্যতম সন্মানীয় সাংস্কৃতিক স্বীকৃতি-২০২৫ চনৰ সংগীত নাটক অকাডেমি বঁটা। বৃহস্পতিবাৰে নতুন দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত আয়োজিত এক গাভীৰূপৰ্ণ অনুষ্ঠানত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ হাতৰ পৰা তেওঁ এই সন্মান গ্ৰহণ কৰে।

নাট্য-অভিনয় শাখাত অসমীয়া নাট্য আৰু পৰিৱেশন কলালৈ আগবঢ়োৱা অসামান্য অৱদানৰ বাবে চেতনা দাসক এই বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰা হয়। দশকজোৰা অভিনয় জীৱনত মঞ্চ, চলচ্চিত্ৰ আৰু বিনোদন জগতত নিজৰ স্বকীয় প্ৰতিভাৰে তেওঁ দৰ্শকৰ হৃদয় জয় কৰি আহিছে। বিশেষকৈ হাস্যৰসাত্মক চৰিত্ৰত তেওঁৰ অনন্য অভিনয়ে তেওঁক অসমৰ ঘৰে ঘৰে



অসমীয়া নাট্য আৰু চলচ্চিত্ৰ জগতৰ বিশিষ্ট শিল্পীগৰাকীৰ দশকজোৰা সাধনালৈ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি

পৰিচিত কৰি তুলিছে।

শিলংত জন্মগ্ৰহণ কৰা চেতনা দাসৰ অভিনয় যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি

হৈছিল ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ নাটক শোণিত কুঁৱৰীৰ জৰিয়তে। সেই আৰম্ভণিৰ পৰাই

অভিনয়ৰ প্ৰতি গভীৰ অনুৰাগ আৰু নিষ্ঠাৰে তেওঁ অসমীয়া নাট্যজগতত নিজৰ এক সুকীয়া স্থান গঢ়ি তোলে। মঞ্চাভিনয়ৰ সমান্তৰালভাৱে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰতো তেওঁ বহুকেইটা স্বৰ্ণৰীণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ বিশেষ মৰম লাভ কৰে।

চেতনা দাসৰ এই সন্মান কেৱল এগৰাকী শিল্পীৰ ব্যক্তিগত সফলতা নহয়; ই অসমীয়া নাট্য আৰু পৰিৱেশন কলাৰ প্ৰতিও এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি। তেওঁৰ অভিনয়ত হাৰাৰসৰ সৈতে সামাজিক সংবেদনশীলতা, চৰিত্ৰৰ গভীৰতা আৰু মঞ্চৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতাৰ এক সুন্দৰ সমন্বয় দেখা যায়।

২০২৫ চনৰ সংগীত নাটক অকাডেমি বঁটাৰ বাবে অসম পৰা চেতনা দাসৰ উপৰি সত্ৰীয়া নৃত্যৰ বিশিষ্ট শিল্পী মল্লিকা কন্দলী আৰু ভাস্কৰ জ্যোতি ওজাকো নিৰ্বাচিত কৰা হৈছিল। সংগীত, নৃত্য, নাট্য আৰু অন্যান্য পৰিৱেশন কলাৰ ক্ষেত্ৰত অসামান্য অৱদান

আগবঢ়োৱা শিল্পীসকলক দেশৰ এই সন্মানীয় বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হয়।

সংগীত নাটক অকাডেমিৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ বৈঠকৰ পিছত ২০২৫ চনৰ বঁটাপ্ৰাপকসকলৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছিল। বঁটাৰ সৈতে প্ৰতিগৰাকী সন্মানপ্ৰাপকক তাম্ৰপত্ৰ, অংগবাস্ত্ৰ আৰু এক লাখ টকাৰ নগদ ধন প্ৰদান কৰা হয়।

চেতনা দাসৰ এই ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মানে অসমীয়া সাংস্কৃতিক জগতত আনন্দৰ টো তুলিছে। দীৰ্ঘদিন ধৰি মঞ্চ আৰু ৰূপালী পৰ্দাৰ জৰিয়তে অসমীয়া ভাষা, সংস্কৃতি আৰু নাট্য পৰম্পৰাক সমৃদ্ধ কৰি অহা শিল্পীগৰাকীৰ এই স্বীকৃতি নতুন প্ৰজন্মৰ শিল্পীসকলৰ বাবেও এক অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ ৰহিব।

চেতনা দাসৰ বঁটা লাভে আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে-শিল্পীৰ সৃষ্টিশীল সাধনাৰ কোনো সীমা নাই; নিষ্ঠা, প্ৰতিভা আৰু সময়ৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ কৰিহি এদিন ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি লাভ কৰেই।

## ছেনিটাৰী পেডত আচলতে কি থাকে ?

ঋতুস্ৰাৱ মহিলাৰ জীৱনৰ এক ষাভাৰিক শাৰীৰিক প্ৰক্ৰিয়া। কিন্তু ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা ছেনিটাৰী পেডৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াও বহু মহিলাই কেৱল শোষণ ক্ষমতা, আকাৰ আৰু লিক্জে ৰোধৰ ওপৰতে অধিক গুৰুত্ব দিয়ে। চিকিৎসকসকলে এতিয়া পৰামৰ্শ দিছে-পেড ক্ৰয় কৰাৰ আগতে ইয়াত ব্যৱহৃত সামগ্ৰী, সুগন্ধি, ছালৰ সৈতে সংস্পৰ্শত থকা উপাদান আৰু বায়ু চলাচলৰ সুবিধাৰ বিষয়েও সজাগ হোৱা উচিত।

এটা ছেনিটাৰী পেড সাধাৰণতে বহু স্তৰেৰে গঠিত। ইয়াৰ ওপৰৰ স্তৰটো দীঘল সময় ধৰি সংৱেদনশীল ছালৰ সংস্পৰ্শত থাকে। সেয়েহে এই স্তৰত ব্যৱহৃত সামগ্ৰীয়ে অক্সিজেন, ঘাম, জ্বলা-পোৰা বা সংৱেদনশীল ছালৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, সুগন্ধিবিহীন, ছালৰ বাবে তুলনামূলকভাৱে কোমল আৰু বায়ু চলাচল কৰিব পৰা পেড বাছনি কৰাটো উপযোগী হ'ব পাৰে।

‘ব্ৰেথেবল’ পেডৰ প্ৰতি  
বাঢ়িছে আগ্ৰহ

বৰ্তমান বজাৰত ‘ব্ৰেথেবল’ বা বায়ু চলাচল কৰিব পৰা ছেনিটাৰী পেডৰ প্ৰচাৰ বৃদ্ধি পাইছে। এনে পেডৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে আৰ্দ্ৰতা

আৰু জলীয় বাষ্প বাহিৰলৈ ওলাই যোৱাৰ কিছু সুবিধা প্ৰদান কৰা, যাতে দীঘলীয়া সময় ব্যৱহাৰৰ সময়ত অস্বস্তি কমে।

দিল্লীৰ এগৰাকী স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ ৰিচা সিংহলৰ মতে, মহিলাসকলে পেড বাছনি কৰাৰ সময়ত কেৱল শোষণ ক্ষমতা আৰু আকাৰলৈ নাচাই ইয়াত ব্যৱহৃত সামগ্ৰীৰ মানদণ্ড, ছালৰ সৈতে সামঞ্জস্য আৰু অতিৰিক্ত সুগন্ধি আছে নে নাই সেই বিষয়েও লক্ষ্য কৰা উচিত।

বিশেষকৈ সংবেদনশীল ছাল থকা মহিলাসকলৰ বাবে ডাৰ্মাট’লজিকেলভাৱে পৰীক্ষিত আৰু অযথা সুগন্ধিবিহীন সামগ্ৰী অধিক উপযোগী হ'ব পাৰে।

মৰিঙা-মুক্ত পেডৰ নতুন চৰ্চা

ঋতুস্ৰাৱৰ সামগ্ৰীৰ বজাৰত এতিয়া উদ্ভিদজাত উপাদানৰ ব্যৱহাৰো দেখা গৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত মৰিঙা বা চৰ্জি গছৰ পাতৰ পৰা লাভ কৰা Moringa oleifera বিশেষভাৱে চৰ্চালৈ আহিছে।

মৰিঙাত বিভিন্ন ভিটামিন, এণ্টিঅক্সিডেণ্ট আৰু উদ্ভিদজাত যৌগ থাকে। বৈজ্ঞানিক গৱেষণাত ইয়াৰ এণ্টিঅক্সিডেণ্ট, প্ৰদাহ-ৰোধী আৰু

কিছুমান জীৱাণু-ৰোধী গুণৰ বিষয়ে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। এই কাৰণে তেওঁ কিছুমান নিৰ্মাতাই ছেনিটাৰী পেডৰ ওপৰৰ স্তৰত মৰিঙাৰ নিষ্কাশিত উপাদান ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। অৱশ্যে চিকিৎসকসকলে স্পষ্ট কৰি দিছে যে কোনো উদ্ভিদজাত উপাদান থকা বাবেই পেড এটোক স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে ‘অধিক স্বাস্থ্যকৰ’ বুলি ধৰি ল'ব নালাগে। সামগ্ৰিকভাৱে সামগ্ৰীৰ গুণগত মান, নিৰাপত্তা আৰু ব্যৱহাৰৰ পদ্ধতিহে অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ।

পেড সলনি কৰাটো

আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ

নতুন প্ৰযুক্তি, ব্ৰেথেবল সামগ্ৰী বা উদ্ভিদজাত উপাদানে পেডৰ ব্যৱহাৰ অধিক আৰামদায়ক কৰি তুলিব পাৰে। কিন্তু ইয়াৰ কোনোটোৱেই মৌলিক ঋতুস্ৰাৱকালীন পৰিচ্ছন্নতাৰ বিকল্প নহয়। চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত পেড সময়মতে সলনি কৰা, ব্যক্তিগত পৰিচ্ছন্নতা বজাই ৰখা আৰু দীঘলীয়া সময় একোটা পেড ব্যৱহাৰ নকৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। পেড ব্যৱহাৰৰ পিছত হাত ভালদৰে ধোৱা আৰু ব্যৱহৃত পেড সঠিকভাৱে মেৰিয়াই নিৰাপদভাৱে পেলোৱাটোও সমানেই প্ৰয়োজনীয়।





VOICE OF ALL, FOR ALL

WEEKLY

# JAN JAN VICHAR

Guwahati, Friday, 14 August 2026



## Parliament's Poor Productivity

Jan Jan Vichar

... New Delhi

The Monsoon Session of Parliament has ended, but the questions surrounding its functioning are likely to remain. According to the figures cited in the report, Rajya Sabha recorded only 39.17% productivity, while Lok Sabha functioned at around 19%. The Rajya Sabha Chairman reportedly said that the Upper House worked for only 37 hours and 49 minutes.

If Parliament were a classroom and productivity were its examination score, these figures would hardly qualify as satisfactory. But Parliament is not a classroom, and its real test is not merely the number of hours it sits. Its success lies in how effectively elected representatives debate legislation, question the government, raise public grievances and hold the executive accountable. The disturbing question, therefore, is not simply who is responsible for the disruption—the government or the Opposition? The larger question is: who ultimately pays the price?

**Parliament must remain functional**

An Opposition has every right



to protest. It is its constitutional and political responsibility to question the government on issues concerning citizens. Whether the issue is the treatment of protesting students, the NEET controversy, allegations relating to the Ram Mandir donations, unemployment, education, healthcare or any other matter, Parliament must provide space for scrutiny.

But there is a fundamental difference between protesting inside Parliament and preventing Parliament from functioning. If repeated disruptions result in Question Hour, Zero Hour and substantive debates being lost, the Opposition may actually weaken the very institution

through which it is supposed to challenge the government.

A powerful question asked on the floor of Parliament becomes part of the national record. A slogan shouted during an adjournment often disappears with the day's headlines.

**The people's questions that remained unheard**

The figures cited in the report present a particularly worrying picture of the Rajya Sabha. Of the 285 starred questions reportedly scheduled, only 16 could be taken up. Similarly, of the 380 subjects intended for Zero Hour and 380 matters listed for Special Mentions, only 52 and 93 respectively

could be taken up. Behind every parliamentary question, however, there is usually a real-world concern.

A question about a railway line may represent an entire region waiting for connectivity. A question about a hospital may concern thousands of patients. A question about employment may represent an unemployed young person. A question about agriculture may concern hundreds of farming families.

When Parliament is disrupted, it is not merely MPs whose voices are lost. The voices of their constituents are lost with them.

**Government too must accept responsibility**

However, it would be unfair to place the entire blame on the Opposition. The government commands the majority, controls the legislative agenda and has the institutional responsibility to ensure that Parliament functions effectively. If an important issue is generating public anger, the government's best response should be engagement, explanation and debate—not merely waiting for the controversy to disappear. Even when the Opposition is unreasonable, the government must demonstrate

**Continued on page 16**

## Parliament Must Be a Forum for Answers, Not Avoidance

Jan Jan Vichar

... New Delhi

Congress MP Gaurav Gogoi's sharp criticism of Union Home Minister Amit Shah over his reported absence during much of the Monsoon Session has triggered a significant debate about parliamentary accountability. Gogoi accused Shah of remaining away from the House for most of the session and "waking up" only two days before its conclusion, particularly when the Opposition was demanding answers on issues including the Jantar Mantar protest and the NEET controversy.

The language used by



the Congress leader—comparing the Home Minister's alleged absence to "Kumbhakarna-like sleep"—is undoubtedly political rhetoric. But beneath the rhetoric lies a serious democratic question: When the Opposition seeks answers on matters of public concern, should the government

not be prepared to respond directly on the floor of Parliament?

According to the report, Shah later expressed willingness to participate in a discussion on the NEET-related protests and asked Lok Sabha Speaker Om Birla to consult the Opposition regarding the timing.

The government's position, as cited in the report, was that the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026 had already been discussed and that Opposition members had not raised the NEET issue during that debate.

That explanation, however, does not entirely settle the larger issue. Parliament is not merely a place for passing legislation; it is the country's principal forum for questioning the executive.

At the same time, the Opposition too has a responsibility. Criticism must remain issue-based, factual and constructive. Parliamentary democracy cannot function if every disagree-

ment becomes a political confrontation.

The real test, therefore, is not whether Amit Shah attended every debate or whether Gaurav Gogoi's criticism was politically sharp. The real test is whether Parliament remained accessible to questions, accountable to citizens and capable of producing meaningful answers.

India needs a Parliament where the government does not fear questions and the Opposition does not fear answers. Democracy becomes stronger not when the ruling side avoids criticism, but when it has the confidence to face it.

## Zubeen Garg Death Case Bail Hearing Inconclusive Next Hearing on September 3

Jan Jan Vichar  
...Guwahati

The bail hearing of accused Sandipan Garg and Amritprabha Mahanta in the case relating to the death of renowned Assamese singer Zubeen Garg remained inconclusive before the Gauhati High Court on Thursday.

The matter was heard before Justice Anjan Jyoti Kalita, who fixed September 3 as the next date of hearing on the separate bail pleas filed by Sandipan Garg and Amritprabha Mahanta.

During Thursday's proceedings, the High

Court directed that relevant documents pertaining to the case pending before the fast-track court be placed before it for consideration. The direction is expected to assist the court in examining the circumstances and legal issues arising from the case while considering the bail applications.

Sandipan Garg and Amritprabha Mahanta have approached the High Court separately seeking relief in connection with the case. Meanwhile, the court has scheduled August 17 for hearing the applications filed by two other accused, Siddhartha

Sharma and Shyamkanu Mahanta.

The proceedings have attracted considerable public attention as the investigation and subsequent legal proceedings in the Zubeen Garg death case continue. The separate bail petitions of the accused are now being considered by the High Court, with the next significant hearing on the pleas of Sandipan Garg and Amritprabha Mahanta scheduled for September 3.

The court's proceedings and the documents placed before it are expected to remain closely watched as the case moves forward.

## Manipur Pays Tribute to Heroes of 1891 Anglo-Manipur War

**Imphal :** Manipur observed Patriots' Day on Thursday, paying tribute to the heroes who sacrificed their lives defending the state's sovereignty during the Anglo-Manipur War of 1891. Governor Ajay Kumar Bhalla and Chief Minister Yumnam Khemchand Singh led the tributes at various memorial sites, including Kangla Utra and Shaheed Minar. Ministers, MLAs, senior officials and security personnel also paid homage to the martyrs, while a contingent of Manipur Rifles presented a Guard of Honour.

Governor Bhalla remembered Yuvraj Bir Tikendrajit, Thangal General and Maharaj Kulachandra, among other patriots, and said their courage and sacrifice remained an important part of Manipur's collective memory. He urged people to preserve the state's history, culture and heritage while strengthening peace, unity and harmony among communities.

Chief Minister Khemchand Singh also recalled the sacrifices of the 1891 heroes and urged the younger generation to carry forward their legacy. He highlighted the achievements of Manipuri sportspersons and other achievers who have brought recognition to the state at national and international levels.

Continued from page 15

### Parliament's Poor...

political maturity and find ways to bring the House back to business.

The fact that several Bills were passed amid disruptions should also concern the government. Passing legislation is not the sole measure of parliamentary success. Good laws require informed debate, scrutiny, amendments and the recording of dissent.

If Opposition members have serious objections to a Bill, Parliament should provide them an opportunity to place those objections on record.

#### Passing Bills is not the same as parliamentary democracy

The report notes that 12 Bills were passed during the session. That may be an achievement from the government's legislative perspective, but legislation passed without adequate discussion raises a larger institutional concern. Whether the subject is examination reform, tribunal reforms, cooperative institutions, banking evidence or mining and minerals, legislation can affect millions of citizens. The question is not whether Parliament should pass laws-it must. The question is whether it should pass them after adequate scrutiny and meaningful debate.

The referral of the FCRA amendment Bill to a Joint Committee for detailed examination demonstrates that parliamentary mechanisms for disagreement and scrutiny already exist. The challenge is to use these mechanisms more effectively instead of turning every disagreement into a confrontation.

**No work, no pay'  
-a debate worth having?**

Another uncomfortable question is whether there should be stronger accountability for persistent disruption. The principle of "no work, no pay" is often invoked in public debate. If an employee deliberately refuses to perform assigned duties, questions about remuneration naturally arise. Parliament, of course, is different from an ordinary workplace, and MPs enjoy special constitutional privileges that protect legislative functioning and free expression. Yet those privileges cannot logically mean that elected representatives have no responsibility toward the public. Any proposal to link attendance or disruption with remuneration would need careful constitutional and parliamentary consideration. But the larger principle deserves discussion: should taxpayers continue to bear the full cost when Parliament repeatedly fails to perform its core functions?

#### The Opposition must also examine its strategy

The Opposition's strongest weapon is not disruption; it is argument. If the government is wrong, expose it with facts. If a policy hurts citizens, demonstrate its consequences. If a minister has failed, demand an explanation. If a Bill is defective, propose amendments and record objections. A functioning Parliament gives the Opposition something far more valuable than a street protest: an official national platform. When the House is adjourned repeatedly, that platform disappears. The Opposition must therefore ask itself whether prolonged disruption actually strengthens its political position or merely allows the government to claim that it was prevented from conducting legislative business.

#### The government cannot escape scrutiny either

The ruling side must also resist the temptation to treat parliamentary majorities as a sub-

stitute for parliamentary debate. A majority can pass legislation, but it cannot manufacture public confidence. That comes from transparency, accountability and persuasion. The government should make every effort to facilitate discussion on contentious issues and respond to legitimate concerns. Important Bills deserve sufficient time for scrutiny. Ministers should be available to answer questions, and parliamentary committees should be used more extensively. A government confident in its policies should have no reason to fear questions.

#### The real report card belongs to both sides

The Monsoon Session should therefore not become another occasion for the government and Opposition to exchange accusations. The Opposition cannot claim democratic virtue merely because it protests. The government cannot claim parliamentary success merely because Bills are passed. Both sides must answer to the people. India's Parliament is not an arena where one side must defeat the other. It is an institution where disagreement is supposed to produce better decisions. The people did not elect MPs merely to raise slogans. Nor did they elect the government merely to use its majority. They elected representatives to debate, question, legislate and solve problems. The productivity figures from this session should therefore be treated not as a political weapon but as a warning. If Parliament repeatedly becomes dysfunctional, public frustration may eventually turn into something far more serious than anger at individual MPs—a loss of faith in the parliamentary process itself. And that is the one defeat that neither the ruling party nor the Opposition can afford.

The final question is simple: If Parliament is the voice of the people, who will answer when that voice is silenced by disruption?



# Sukhbir Singh Badal Attacked in Nanded

— Jan Jan Vichar  
... Nanded

Former Punjab Deputy Chief Minister and Shiromani Akali Dal president Sukhbir Singh Badal was injured in a knife attack near Takht Sri Hazur Sahib in Nanded on Thursday morning.

The incident occurred around 11:30 a.m., when Badal was on his way to the gurdwara. According to reports, an attacker approached him and attempted to stab him with a sharp-edged weapon. Police personnel immediately intervened and overpowered the assailant, but Badal sustained an injury to his hand. A police personnel was also injured during the incident.

Badal was subsequently



taken to a private hospital for medical treatment. Police detained the attacker and have begun questioning him to determine the motive behind the assault.

The incident has raised serious concerns over security arrangements around prominent political and religious figures, particularly at a sensitive religious site. The attack at the gurdwara premises also raises ques-

tions about how the assailant managed to approach a former Deputy Chief Minister despite the presence of security personnel.

Sukhbir Singh Badal, son of former Punjab Chief Minister Parkash Singh Badal, is a prominent leader of the Shiromani Akali Dal. Authorities are investigating the circumstances surrounding the attack and the motive of the accused.

## DMK May Join NDA Cabinet Expansion Likely

— Jan Jan Vichar  
... New Delhi

Signs of a major political realignment are emerging at the Centre, with the DMK reportedly in talks to join the NDA and secure representation in the Union Cabinet. The development could significantly alter the political equations ahead of key constitutional and electoral reforms.

According to reports, final-stage discussions are underway between the BJP and the DMK, while a possible Cabinet expansion could take place later this month. The NCP faction led by Sharad Pawar is also reportedly showing signs of moving closer to the

NDA. The possibility of bringing the Shiromani Akali Dal back into the alliance is also being explored.

The reported move is being linked to the government's efforts to

rial berth for Supriya Sule.

If the reported numbers materialise, the NDA and its allies could have around 355 members in the Lok Sabha, just five short of the two-thirds mark of 360. In the Rajya



build wider support for constitutional amendments related to delimitation and the early implementation of women's reservation.

The DMK, which has 22 Lok Sabha and eight Rajya Sabha members, is reportedly seeking two ministerial positions. The NCP may seek a ministe-

Sabha, the alliance could reach about 163 members, only one short of the 164 required.

If these talks succeed, the political landscape could witness one of the most significant realignments in recent years, potentially putting further pressure on the Opposition bloc.

### NEWS IN BRIEF

## Bihar's 688 Model Schools to Offer 24×7 Online Teacher Support



**PATNA:** Students in 688 model schools across Bihar will soon have access to teachers online round the clock, under a new interactive learning initiative being introduced by the Bihar School Examination Board (BSEB). The initiative will

allow students of Classes 9 to 12 to connect with teachers online at any time and seek answers to subject-related questions. The service will be available 24 hours a day, seven days a week, and will be provided free of cost. Students will need to register through the designated portal or mobile application. After registration, they can select their class and subject and join live online sessions. Students will also be able to send questions to teachers through messages and receive detailed explanations and solutions.

The initiative aims to provide students with quick answers as well as personalised guidance to improve their learning. It will enable students to seek teachers' assistance even after regular school hours, particularly when they face difficulties while studying at home. The examination board has directed district education officers to coordinate with school principals to ensure effective implementation of the programme.

In Patna, the facility is being introduced in 11 model schools and PM Shri Bankipur Girls' Higher Secondary School, benefiting students from Classes 9 to 12. The initiative is being seen as an important step towards expanding access to academic support through technology and ensuring that students can receive expert guidance whenever they need it.

## Chamoli Tunnel Accident Raises Serious Safety Questions

**Chamoli (Uttarakhand):** A major accident at the under-construction tunnel of the Vishnugad-Pipalkoti hydropower project in Chamoli has claimed seven workers' lives, while three others remain missing. Around 28 workers were reportedly trapped after a sudden surge of water and debris entered the tunnel; 18 were rescued. The incident has raised serious questions over worker safety and accountability. More concerning, the contractor, Hindustan Construction Company (HCC), reportedly could not provide a clear count of workers inside the tunnel for several hours. Initial figures varied between 24 and 28, raising concerns about the adequacy of worker records and emergency preparedness.

The tragedy has also revived memories of the Silkyara-Barkot tunnel accident in Uttarakashi in November 2023, when 41 workers were trapped underground for 17 days before a challenging rescue operation brought them to safety. The Chamoli incident highlights the urgent need for strict safety protocols, accurate worker tracking and clear emergency-response systems at major infrastructure projects. For the families waiting for their loved ones, every minute matters—and accountability cannot be delayed.

## EDITORIAL FCRA Bill

The decision to refer the Foreign Contributions (Regulation) Amendment Bill, 2026 to a Joint Parliamentary Committee (JPC) is a welcome and sensible step. A law governing foreign contributions must protect national interests and financial transparency, but it must also ensure that genuine institutions engaged in social, educational and charitable work are not subjected to arbitrary action. There is little dispute over the need for stronger oversight of foreign funds. The government has a legitimate responsibility to ensure that such money is used

transparently and strictly for lawful purposes. However, regulation must not become a tool for creating fear among organisations that have maintained a clean record and genuinely serve society.

The most troubling aspect of the proposed legislation is the provision allowing the government to take over assets or facilities created with foreign funding when an organisation loses its FCRA registration under certain circumstances. Such sweeping powers, particularly without adequate judicial oversight, could place institutions at the mercy of executive discretion. A system in which the executive effectively becomes complainant, decision-maker and enforcer raises seri-

ous questions of fairness.

Union Home Minister Amit Shah's assurance that the legislation will have no retrospective effect is reassuring. Nevertheless, the JPC must examine the proposed provisions relating to expired registrations, renewal applications and possible government takeover of assets. The objective should be neither to weaken national security nor to burden genuine institutions. The committee must strive for a balanced law—strong enough to prevent misuse of foreign funds, yet fair enough to protect legitimate organisations from unnecessary harassment. Good legislation is not merely about control; it is about accountability with justice.

# Pak-Saudi-Turkish Pact A Fresh Challenge For India

Jan Jan Vichar  
... K.C. Singh

A trilateral mutual defence agreement was signed between Turkey, Saudi Arabia and Pakistan in Mecca. The venue, which has Islam's holiest mosque, symbolises a convergence of three powerful Islamic nations. The mutual defence clause reflects Article 5 of the Nato agreement. Though Egypt had joined the negotiations earlier, it kept away. Turkey's foreign minister, Hakan Fidann, expects it to join soon. Turkish leaders emphasised that the agreement was not aimed at any country and was a purely defensive measure.

Though not a "Middle Eastern Nato", some term it the "Islamic Nato". Members of Nato had shared concerns about countering the Soviet Union and the Warsaw Pact countries. In fact, their joining the 2001 US intervention in Afghanistan went beyond the original mandate. Also, Nato countries have a joint command and control system and a shared nuclear deterrence, though the US retains the control of forward-deployed nuclear weapons. The three Mecca agreement nations have some, not totally, overlapping threat concerns. Turkey has had differences with Israel. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu even declared that "our next target is Turkey". Consequently, Turkish President Recep Tayyip Erdogan announced that "now you can't even touch our hair". Turkey has berated Israeli military intrusions into Lebanon and pressure on the Syrian regime, which Turkey helped install. Turkey's relations with Iran have fluctuated. But they share an interest in containing the aspirations of the

Kurdish community which dominates eastern Turkey, the northern parts of Syria and Iraq as well as western Iran. Reportedly, Turkey restrained Israel from employing Iraqi Kurds for a ground operation against Iran, co-opting Iran's Kurdish minority, at the start of the US-Israeli war.

Ironically, the Turkish Ottoman Empire, after recapturing Diriyah, the first Saudi state, in 1818, took the al-Saud family ruler and his sons prisoner. They were beheaded in Istanbul, then Constantinople, in 1818. Recent Saudi-Turkish differences first arose over Turkey supporting the Arab Spring in 2010-11. Then came the brutal killing of American journalist Jamal Khashoggi in the Saudi consulate in Istanbul. Now the shared threats eclipse the past differences.

Winning strategies Saudi Arabia basically perceives a threat from Iran and its allies like Yemen's Houthis and Iraq's pro-Iran militias. Yemen has had a truce since 2022, but recently the Houthis targeted Saudi Arabia's Aramco oil facility. Regarding Israel, the Saudis have resisted US pressure to sign the 2020 Abraham Accords and normalise relations, demanding that Israel must first present a pathway to a Palestinian state. In fact, the Saudis hurriedly signed a mutual defence agreement with Pakistan in September 2025, days after Israel targeted Hamas in Qatar, which created a perception of the US being unable or unwilling to control Israel targeting the GCC countries. However, the US-Israeli airstrikes on Iran on February 28 triggered the Iranian retaliation on US military bases and assets in the GCC nations. Thus, the present Mecca agreement covers

Saudi Arabia's perceived threats from both Israel and Iran plus its allies. Pakistan presents a different case. Since independence, it has repeatedly tried grabbing the India-controlled Jammu and Kashmir by force or multilateral UN intervention or terrorism-based blackmail. After 1947, while India chose nonalignment during the Cold War, Pakistan accepted military alliances with the US and Britain. In 1954, it signed the mutual defence assistance agreement with the US for obtaining military assistance in exchange for an anti-Communist posture. The new Air Force aircraft and the Army's tanks gave Pakistan a military advantage over India, which instead was focused on development and not strengthening its defence forces. China militarily defeating India in 1962 and the 1964 death of Prime Minister Jawaharlal Nehru left the Indian defence forces demoralised and under-equipped. Perceiving Indian vulnerability, Pakistan tried in 1965 to militarily grab Kashmir, but failed. The military alliance with the United States slowly weakened after Pakistan declined to send troops to assist America during the Vietnam War. It eventually collapsed after India won the 1971 war, leading to the creation of Bangladesh. Pakistan since then has aligned with China as both countries want to contain India while keeping their outstanding disputes alive. In between, Pakistan again became the military spearhead of the US-Saudi countering of the Soviet military intervention in Afghanistan in 1979. In the new trilateral arrangement, the Saudis bring oil wealth and religious standing; Turks contribute a modern army and weapons compliant with Nato

standards; and Pakistan represents the only Islamic nation possessing nuclear weapons. But the "mutual defence" commitment has limits. Iran's recent targeting of Saudi Arabia, over the existence of US military bases on its soil, saw Pakistan continuing to play the mediator without threatening Iran with retaliation. Similarly, in Pakistan's standoff with the Afghan Taliban regime, the Saudis have maintained neutrality, perhaps helping financially or by military supplies. How does the Mecca agreement impinge on Indian interests? Firstly, the Indian policy of military retaliation for Pakistan-sponsored terror attacks in India requires reassessment. The Iran war has demonstrated the failure of US airstrikes to intimidate Iran. The 2025 Operation Sindoor was an enhanced version of the 2019 Balakot airstrikes. And yet, Pakistan was not deterred. Saudi Arabia and Turkey are unlikely to openly join Pakistan if India undertakes such an operation again. Though in the past, Turkey had supplied advanced drones to Pakistan, both may now openly transfer arms. But between US President Donald Trump's pampering of Pakistan's military and civilian leadership, Pakistan's Iran war mediation and now the Mecca agreement, both the global and the regional diplomatic standing of Pakistan has risen. Closer engagement between the defence industries of Pakistan and Turkey, with Saudi financial backing and Chinese technological assistance, could present India with a stronger and economically revived antagonist. Persisting with non-dialogue with Islamabad, as even the RSS has argued, is a fairly poor diplomatic strategy.



# When the Colours Fade: Tripura's 'Alpana Gram' Seeks a New Lease of Life

Jan Jan Vichar

... Agartala

A few kilometres from Agartala, close to the Bangladesh border, lies a village that once transformed itself into a living canvas. Lankamura, earlier known as Lankamura Kapali Para, gradually became famous as 'Alpana Gram', attracting visitors with its colourful traditional wall paintings and folk-cultural identity.

Today, however, the colours that once gave the village a distinctive place on Tripura's tourism map are slowly fading. Along with the paintings, villagers say, the flow of tourists and the economic opportunities that came with them have also declined.

For more than 150 families living in the village, the concern is not merely about losing a few paintings on mud walls. The alpana tradition has become closely linked with their cultural identity, community participation and livelihood. Residents are now appealing to the government to revive the village as a cultural and rural tourism destination.

## From an ordinary village to 'Alpana Gram'

The transformation began in 2020 when a folk-culture workshop was organised with financial support from the Government of India's Eastern Zonal Cultural Centre and the initiative of Sanskar Bharati Tripura.

During the programme, artists decorated the mud walls of village homes with traditional alpana designs. The colourful patterns, drawn from local artistic traditions, gave the village a completely new appearance and highlighted the rich folk heritage of the region.

The initiative soon attracted attention beyond the village. Visitors from different parts of Tripura and other states began arriving to see the distinctive artwork. The village found a place on the tourism map, while residents discovered new possibilities for earning an additional income.

Local people began selling handmade products, vegetables, traditional snacks and other items to visitors. For many families, tourism became an important supplementary source of income.



## A cultural identity that brought economic hope

According to resident Amrit Sarkar, the transformation changed the way people outside the village viewed Lankamura. He recalled that the area was earlier known as Lankamura Kapali Para, but gradually became recognised as Alpana Gram. He credited Sanskar Bharati with playing an important role in creating the village's new cultural identity.

Visitors from different parts of India and even abroad came to see the traditional artwork, he said.

The annual three-day Pitha-Puli festival, organised around Makar Sankranti, further strengthened the village's cultural appeal. The festival offered local families an opportunity to showcase their traditions while earning from the sale of pitha, vegetables, handicrafts and other local products.

For a village largely dependent on flower cultivation, vegetable farming and small businesses, these opportunities mattered.

## When the tourists stopped coming

The situation, however, has changed in recent years. Villagers say tourist footfall has declined considerably, reducing the income they once earned during festivals and other busy periods. The enthusiasm surrounding the alpana tradition has also weakened.

Resident Malati Kapali remembers a time when almost every

house participated in decorating the village during Poush Sankranti. During the Alpana festival, we used to sell pitha, vegetables and other products. Many people came, and we were very happy. Earlier, every house was decorated with alpana and everyone participated. But now fewer tourists visit and our income has reduced," she said.

For the residents, the decline in visitors represents more than a fall in sales. It threatens the community spirit that once brought people together around their traditional art.

Another resident, Arati Sarkar, said that during the festival season villagers could earn by selling vegetables and other products and by creating alpana designs. Today, she said, very few visitors come. She believes government intervention could help restore the village's tourism potential and create economic benefits for local families.

## More than paintings on a wall

What makes Alpana Gram significant is that its artwork is not simply decorative. The paintings represent the cultural memory of the community. They connect generations with local traditions and provide a visual expression of the village's identity. At the same time, they demonstrate how cultural preservation can be linked with rural economic development.

The experience of Lankamura shows that even a small village can attract visitors when its local culture is presented creatively. But

such initiatives require continuous support, maintenance and promotion if they are to remain sustainable.

## A call for revival

Villagers are now hoping for renewed government attention to the development of Alpana Gram. They want the cultural initiative to be revived and the village to receive greater tourism promotion and basic facilities capable of attracting visitors throughout the year. Regular cultural festivals, restoration of faded wall paintings, promotion of local handicrafts and traditional food, better visitor facilities and stronger publicity could help revive the village's appeal.

The government could also explore ways of involving local artists, women's groups and small entrepreneurs so that tourism generates direct and sustainable income for the community.

For the people of Alpana Gram, the fading colours on their walls carry a larger message. They represent a tradition that gave their village recognition and opened a window of economic opportunity.

If timely steps are taken, Lankamura can once again become a vibrant example of how culture, community participation and rural tourism can work together. If nothing is done, however, the colours may disappear one wall at a time and with them, a unique chapter of Tripura's folk-cultural identity may slowly fade from public memory.

## Pawan Singh Praises Amrapali



**Mumbai:** Bhojpuri superstar Pawan Singh has publicly praised actress Amrapali Dubey for expressing her desire to adopt a child. His heartfelt message has touched the actress, who responded with an emotional note thanking him for standing by her as a friend and source of strength.

The conversation emerged after Amrapali spoke about her wish to adopt a child on the reality entertainment show Bhojpuri Bawal. Pawan Singh, who affectionately calls her "Pandit Ji," shared a post praising her decision. He described adoption as much more than simply welcoming a child, saying it means embracing an entire life, and saluted her for the "beautiful decision."

Amrapali subsequently reposted Pawan Singh's message on Instagram and expressed her gratitude. She thanked him and said that having a supportive family and friends like him gives her confidence that her decisions will succeed. She also wrote that she would always remain grateful for their friendship and for the support that has given her courage.

## Preity Zinta Returns to the Beginning with Batwara 1947

**Mumbai:** As Batwara 1947 arrives in cinemas on August 14, actress Preity Zinta has taken audiences back to the moment when her journey with the film first began. Ahead of the release, she shared a black-and-white look-test photograph of her character Hamida, accompanied by an emotional reflection on the role.

The photograph captures Zinta during the early stage of her transformation into Hamida. Sharing the image on social media, the actress said she wanted to return to the place "where everything began" just before the film reached theatres. For her, the look test was the moment when she first saw and experienced Hamida as a character.

Zinta also used a line attributed to the celebrated Persian poet Rumi to describe Hamida's spirit: when everything around appears dark, one should look again



because the light may be within oneself. The thought reflects the emotional strength and resilience associated with her character against the backdrop of one of the most painful chapters in the subcontinent's history.

Directed by Rajkumar Santoshi and produced by Aamir Khan, Batwara 1947 is set against the backdrop of the Partition of India in 1947. The film fea-

tures an ensemble cast including Sunny Deol, Preity Zinta, Shabana Azmi, Ali Fazal and Karan Deol, with appearances by Aamir Khan and other prominent actors.

For Zinta, the film marks a significant return to the big screen, while her portrayal of Hamida places her within a story shaped by displacement, loss, hope and human resilience.

## Rani Mukerji: Three Decades of Cinema, Courage and Characters That Endure

**Melbourne:** Indian cinema celebrated one of its finest performers as Rani Mukerji was honoured at the Indian Film Festival of Melbourne (IFFM) 2026 with a special citation for Excellence in Acting. The honour recognises her remarkable three-decade journey, memorable performances and enduring connection with audiences across the world.

Rani Mukerji's career stands out for its remarkable diversity. From romantic dramas and youthful entertainers to powerful stories centred on women, she has repeatedly chosen characters that demanded emotional depth, conviction and courage. Her perfor-



mances have not merely entertained audiences; many have challenged social conventions and brought complex women to the centre of the story.

Her impressive body of

work includes acclaimed films such as Black, Hum Tum, Yuva, Bunty Aur Babli, No One Killed Jessica, Hichki, the Mardaani franchise and Mrs. Chatterjee vs Norway. Across these very different roles, Mukerji has demonstrated an ability to transform herself while retaining an unmistakable screen presence.

Reflecting on the honour, Mukerji said that she never imagined as a young actor that her films and characters would travel across oceans and find affection in countries such as Australia. For her, the greatest reward of cinema is the ability to connect people through stories and emotions that transcend borders.

DS **D.S. ASSOCIATES**  
 TAX CONSULTANTS TRUSTED ADVISORS

**Happy INDEPENDENCE DAY 2026**

Let's honor the past, celebrate the present and build a stronger, prosperous future together.

स्वतंत्रता का सम्मान करें, कर्तव्य का पालन करें, आइए मिलकर एक समृद्ध भारत बनाएं।

**ONE-STOP SOLUTION**  
**ALL YOUR TAX & FINANCE NEEDS UNDER ONE ROOF**  
 Expert, reliable and timely solutions for individuals, businesses & startups — handled by experienced professionals you can trust.

**OUR SERVICES**

- Income Tax Returns
- Audit
- Loans
- Company Registration
- Trademark Registration
- Subsidy Related Works

- GST Registration & Filing
- Accounting & Book Keeping
- Insurance
- Import & Export Compliance
- FSSAI Registration
- Documentation Services

**...AND MANY MORE SERVICES**  
**CONTACT US TODAY**  
 E-Mail : dsataxtax@gmail.com

**Dhaneshwar Choudhary**  
**70026 82705**

**Subhash Choudhary**  
**84728 20656**